घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 281- मंगलवार 11- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज...आंसू गैस के गोले दागे

विधानसभा के 100 मीटर पास पहुंचे,बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश,जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार

रांची,10 अगस्त 2026। झारखंड के रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। वहीं पर धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो छात्रों ने जवाब में पानी की बोतल और चप्पलें फेंकीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंटीले तार की बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की तो छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इधर, सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। 21 जुलाई को जेपीएससी ऑफिस में रेड के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सीआईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। विधानसभा को चारों तरफ से 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं, 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो एंबुलेंस से विधानसभा मार्च में शामिल हुए। भाजपा विधायक भी छात्रों के समर्थन में सीएम हाउस के सामने धरने पर बैठे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से हटा दिया। छात्र झारखंड पीएससी-एसएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 17 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 6 छात्र भूख हड़ताल पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स लिखा- जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते की गिरफ्तारी सिर्फ दिखावा है। हेमंत सरकार विनय चौबे की तरह इन्हें भी बिना चार्जशीट दाखिल किए डिफॉल्ट बेल दिलाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। छात्रों की मांग सिर्फ जेपीएससी तक सीमित नहीं है। जेएसएससी की सहायक आचार्य, सीजीएल, उत्पाद सिपाही और पीजीटी जैसी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली कर नौकरियां बेची गई है।

एम्बुलेंस से विधानसभा घेराव करने पहुंचे देवेंद्रनाथ महतो, समर्थकों ने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ाया

जेपीएससी-जेएसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन सोमवार को 17वें दिन और भूख हड़ताल नौवें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जयपाल सिंह स्टेडियम से एंबुलेंस के जरिए सीधे विधानसभा घेराव मार्च में शामिल होने पहुंचे। एंबुलेंस से उतरते ही उत्साहित छात्र अभ्यर्थियों और समर्थकों ने देवेंद्र नाथ महतो को कंधे पर उठा लिया और उन्हें मार्च में आगे लेकर बढ़े। इस दौरान छात्रों में खासा उत्साह नजर आया। देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की मांगों को पूरी तरह लागू नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा घेराव में झारखंड के अलावा राज्य के बाहर रहने वाले लोग भी शामिल होने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन छात्रों के संघर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। महतो ने आरोप लगाया कि छात्र पिछले 17 दिनों से धैर्य के साथ जयपाल सिंह स्टेडियम में सत्याग्रह कर रहे हैं और सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है।

विधानसभा घेराव में 'पुष्पा भाऊ' का अंदाज बोले...झुकेगा नहीं झारखंड का छात्र

झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सोमवार को रांची में हुए विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शन का एक अलग रंग देखने को मिला। बॉलीवुड अभिनेता के चर्चित किरदार 'पुष्पा राज' के अंदाज में वायरल 'पुष्पा भाऊ' छात्रों के समर्थन में आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई। समयऔर कैलेंडर 'पुष्पा भाऊ' ने कहा कि छात्रों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन को देखकर वह काफी आहत हुए और इसी वजह से उनके समर्थन में झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए कुछ प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा और अश्लील टिप्पणियां सामने आने की बातें कही गई थीं, वैसा माहौल रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सार्वजनिक रूप से चल रही हैं और पूरा देश उन्हें देख-सुन रहा है,लेकिन रांची में चल रहे आंदोलन की वास्तविक तस्वीर भी सामने है।

लोकसभा में 4 बिल पेश हुए,इनमें केरल का नाम केरलम करने वाला बिल शामिल...

जंतर-मंतर लाठीचार्ज मामले पर संसद में जवाब देंगे शाह

विपक्ष को सुनना पड़ेगा,भाग नहीं सकते : किरण रिजिजू

नई दिल्ली,10 अगस्त 2026। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस एक्शन मामले पर सदन में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि शाह विस्तार से जवाब देंगे लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वह बहस से भागेगा नहीं। उन्हें गृहमंत्री का जवाब बिना हंगामा किए सुनना पड़ेगा। हालांकि शाह कब बोलेंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। शाह संसद परिसर में नियमित रूप से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सदन में नहीं देखा गया है। मानसून सत्र 20 जुलाई से चल रहा है। 13 अगस्त को इसका समापन है। तीन हफ्ते के दौरान लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित हुई है।

संसद ने टैक्स बिल को मंजूरी दी सीतारमण ने कहा...यूपीआई लेनदेन रहेंगे मुफ्त

संसद ने सोमवार को'कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक-2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा ने विधयेक पर चर्चा के बाद इसको लोकसभा में वापस भेज दिया। इस विधयेक में विदेशी निवेश के नियमों, डिजिटल पेमेंट (यूपीआई/एमडीआर),कच्चे हीरे के व्यापार में छूट और आरईआईटी/ इनविट्स पर टैक्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसे लोकसभा ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी। समयऔर कैलेंडर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए साफ किया कि यह कानून यूपीआई पर कोई टैक्स नहीं लगाता है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुफ्त बना रहेगा। पिछले हफ्ते लोकसभा से पास हुए इस विधयेक को राज्यसभा ने वित्त मंत्री के जवाब और संक्षिप्त चर्चा के बाद 'वॉइस वोट' (मौखिक मतदान) से वापस भेज दिया।

प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर विपक्ष का संसद परिसर में प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद में बयान देने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक गृह मंत्री इन मुद्दों पर सदन में स्पष्टीकरण नहीं देते,तब तक विपक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा आगे नहीं बढ़ने देगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि गतिरोध तब तक बना रहेगा,जब तक केंद्रीय गृह मंत्री संसद में बयान नहीं देते। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी विपक्ष की मांग को स्पष्ट करते हुए कहा... कि किसी भी विधेयक,जिसमें एफसीआरए बिल भी शामिल है,पर चर्चा से पहले अमित शाह को संसद में आकर दिल्ली के छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की स्पष्ट मांग है और बयान के बिना सरकार को इन मामलों पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। एफसीआरए बिल को लेकर भी विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी इस विधेयक को एक बड़े समुदाय के खिलाफ उठाए गए कदम के रूप में देखती है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित बदलाव समुदाय और देश के हितों के खिलाफ हैं तथा इससे शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में भी गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा।

लोकसभा में 4 बिल पेश हुए, इनमें केरल का नाम केरलम करने वाला बिल शामिल

विपक्षी सांसदों के नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच सोमवार को लोकसभा में चार बिल पेश किए गए। इनमें ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 शामिल हैं। इसके अलावा केरल (नाम में बदलाव) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 भी पेश किए गए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल पेश किया। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल पेश किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 पेश किया। बिल में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने का प्रस्ताव है।

जंतर-मंतर पर फायरिंग का आदेश किसने दिया,जिम्मेदार कौन : राहुल

राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर जंतर-मंतर प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। राहुल ने सवाल किया कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। इसका जिम्मेदार कौन है, वो सामने आए। गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। राहुल ने कहा कि विपक्ष की तीन मांगें हैं। पहली- युवाओं पर गोली चलाने की जिम्मेदारी स्पष्ट हो। दूसरी- प्रधानमंत्री घटना के लिए माफी मांगें और तीसरी- राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर चर्चा हो। जेपी नड्डा ने कहा- जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली। राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। गृहमंत्री हर बात का जवाब देने को तैयार, आप चर्चा से मत भागिएगा। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि शाह सदन में विस्तार से जवाब देंगे लेकिन विपक्ष को भरोसा देना होगा कि वह बहस से भागेगा नहीं। उन्हें गृहमंत्री का जवाब बिना हंगामा किए सुनना पड़ेगा। हालांकि शाह कब बोलेंगे, रिजिजू ने इसकी जानकारी नहीं दी है।

मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में नाले में ईको कार बही,9 लोगों की मौत

राजगढ़,10 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह तेज बारिश के बीच नाले के निर्माणाधीन पुल पर तेज बहाव में ईको कार बहने से ससुर-दामाद के परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों ने तैरकर अपनी बचा ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ग्राम पड़ाना चौकी क्षेत्र में बाइपास स्थित झिरी नाले के निर्माणाधीन पुल पर तेज बहाव में चालक ने ईको कार निकालने का प्रयास किया। इसमें कार पानी में बह गई। कार में कुल 11 लोग सवार थे। इनमें से नौ लोगों की डूबने से मौत हो गयी जबकि दो लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। पुलिस के अनुसार ईको कार में सवार परिवार देवास जिले के सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम कड़लावद धाम जा रहा था। बताया गया कि शंकरसिंह की पत्नी सागरबाई लकवा की बीमारी से पीड़ित थीं। परिवार उन्हें झाड़फूंक कराने के लिए कड़लावद धाम ले जा रहा था। इसी दौरान तेज बारिश के कारण झिरी नाले में पानी का बहाव काफी बढ़ गया था। हादसे में विशाल (27) पुत्र शंकर सिंह चौहान निवासी ग्राम धांसड, शंकर सिंह (50) पुत्र सोहेबू चौहान, पूजा (25) पत्नी विशाल सिंह, सागरबाई (45) पत्नी शंकर सिंह चौहान,महक (2) पुत्री विशाल, वंशिका (3)पुत्री विशाल,रेणू पंवार (28) पत्नी होकम सिंह पंवार,जसप्रीत (5)पुत्री होकम सिंह और राजवीर (3) पुत्र होकम सिंह पंवार निवासी सतवास, जिला देवास की मौत हुई है। वहीं होकम सिंह (40) पुत्र नकल सिंह पंवार और मुकेश (40) पुत्र नानकराम ने तैरकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही एसडीएम रोहित बम्होरे,एसडीओपी अरविंद सिंह और थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। क्रेन की मदद से कार को भी नाले से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पात्र मृतकों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

ई-वीजा धारकों के लिए 11 नये अंतरराष्ट्रीय पारगमन बिन्दु अधिसूचित प्रवेश की सुविधा अब 88 स्थानों पर

नई दिल्ली,10 अगस्त 2026। केंद्र सरकार ने ई-वीजा धारक विदेशियों के भारत में प्रवेश के लिए 11 और अंतरराष्ट्रीय प्रवेश बिन्दुओं को अधिसूचित किया है। इनमें नौ भूमि पारगमन केन्द्र और दो हवाई अड्डे शामिल हैं। इसके साथ ही ई-वीजा धारक विदेशियों के लिए भारत में प्रवेश की सुविधा वाले अंतरराष्ट्रीय पारगमन बिन्दुओं की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में बताया कि नए जोड़े गए 11 पारगमन बिन्दुओं में अगरतला,दरांगा,गेडे, घोजाडांगा, हरिदासपुर,जयगांव,डावकी,मोरेह और अटारी (रोड) भूमि सीमापारगमन केन्द्र तथा भोपाल और तिरुपति हवाई अड्डे शामिल हैं। नए पारगमन बिन्दुओं को शामिल किए जाने से ई-वीजा की उपयोगिता और आकर्षण बढ़ने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार भारत में प्राप्त लगभग 95 प्रतिशत ई-वीजा आवेदनों का निपटारा 72 घंटे से कम समय में किया जाता है। नवीनतम अधिसूचना के बाद ई-वीजा धारक विदेशियों के प्रवेश के लिए अधिसूचित 88 अंतरराष्ट्रीय पारगमन बिन्दुओं में 37 हवाई अड्डे,38 समुद्री बंदरगाह और 13 भूमि पारगमन केन्द्र शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार,प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में वीजा व्यवस्था को उदार, सुगम और सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप,47 की मौत

कई लोग मलबे में दबे,सैकड़ों घायल,इमारतें खाली कराई गईं

कोलंबिया,10 अगस्त 2026। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसमें अब तक 47 लोगों की मौत हो गई हैं। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 7 बजे आया। लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। कई इमारतें खाली कराई गई हैं। सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक,भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में पालमार इलाके में था।

इसके झटके पड़ोसी देश इक्वाडोर और वेनेजुएला तक महसूस किए गए। कोलंबिया दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित देशों में से एक है। यहां हर साल हजार से ज्यादा छोटे-बड़े भूकंप आते हैं। कोलंबिया में बार-बार भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह देश'रिंग ऑफ फायर'नाम के भूकंप और ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में आता है। यहां नाजका,कोकोस और दक्षिण अमेरिकी जैसी कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इनमें से एक प्लेट दूसरी के नीचे धंसती रहती है। इसी वजह से जमीन के अंदर लगातार हलचल होती रहती है, जिससे अक्सर तेज भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। कोलंबिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति एबेलार्डो दे ला एस्प्रिएला ने कहा कि उन्होंने सैन जोस डेल पालमार में भूकंप के बाद सरकार की आपात प्रतिक्रिया की व्यक्तिगत रूप से कमान संभाल ली है। उन्होंने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे अकेले नहीं हैं और सरकार मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई कर रही है।

श्रावण के सोमवार को केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब

14.45 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

रुद्रप्रयाग,10 अगस्त 2026। श्रावण माह के सोमवार के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचते रहे। केदारनाथ धाम में अब तक 14,45,946 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। श्रावण के सोमवार को केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर और यात्रा मार्ग पर भक्तिमय माहौल बना रहा। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में केदारनाथ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। धाम में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रशासन की विभिन्न टीमें लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर तैनात हैं।

संपादकीय

मेटा को चेतावनी

यह अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने इंस्टाग्राम,वाट्सएप और फेसबुक का संचालन करने वाली कंपनी मेटा को यह चेतावनी दी कि उसे भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। इसके साथ ही सरकार ने मेटा से अपने एल्गोरिदम को लेकर भी जवाब तलब किया है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इस निर्देश का वास्तव में पालन हो,क्योंकि मेटा अथवा अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियां एलगोरिदम का मनमाना उपयोग करती हैं।

एआई के आगमन के बाद उनके लिए ऐसा करना और आसान हो गया है। अब यह किसी से छिपा नहीं कि इंटरनेट कंपनियां एक विशेष एजेंडे का प्रचार-प्रसार करती हैं। वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि लोग क्या देखें और क्या नहीं? ऐसा करके वे लोगों के चिंतन को प्रभावित कर रही हैं। चिंताजनक यह है कि यह काम प्राय- संकीर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यह एक तथ्य है कि इंटरनेट कंपनियां कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने का काम कर चुकी हैं।

वे ऐसा भारत में भी कर चुकी हैं और इसका पता कैंब्रिज एनालिटिका मामले से चलता है। वैसे तो इंटरनेट मीडिया कंपनियां अपने को सोशल मीडिया कहती हैं,लेकिन सच यह है कि वे असामाजिक और अराजक तत्वों को भी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। वे ध्रुवीकरण के साथ ही सामाजिक विभाजन की खाई भी चौड़ी कर रही हैं। वे कई बार अपने गलत इरादों की पूर्ति करती हुई पाई गई हैं। हर बार वे माफी मांगकर बच निकलती हैं।

भारत सरकार को अब केवल माफी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई इंटरनेट मीडिया कंपनी अनुचित कार्य करती पाई जाए तो उसे वैसे ही कठोर दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए जैसे अनेक पश्चिमी देश समय-समय पर बनाते हैं और उन पर भारी जुर्माना लगाते हैं। अभी हाल में अमेरिका ने मेटा पर भारी जुर्माना लगाया। इंटरनेट मीडिया कंपनियां दुनिया भर में लोगों को लती भी बना रही हैं।

अभी हाल में मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटाने को लेकर जो माफी मांगी,उसे खारिज कर सरकार ने उचित ही किया। समस्या केवल यह नहीं कि मेटा ने किसी खास एजेंडे के तहत शरारतपूर्ण ढंग से प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाया, बल्कि यह भी है कि उसने यह माना कि उसके प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के साथ-साथ डीपफेक वीडियो को बढ़ावा दिया गया।

यह भी स्वीकारा कि उसने पैसे लेकर हानिकारक सामग्री को बढ़ावा दिया। ये सब ऐसी हरकतें हैं,जिनके लिए मेटा अथवा अन्य इंटरनेट कंपनियों को जवाबदेह बनाना अनिवार्य है। यह सही समय है कि भारत सरकार मेटा एवं अन्य इंटरनेट मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने के साथ ही इस पर भी विचार करे कि आखिर विदेशी इंटरनेट मीडिया कंपनियों पर निर्भर रहना कहां तक उचित है?

भागवत की नजरों में जेन-जी आंदोलन का दृष्टिकोण

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

जंतर-मंतर से उठी हाल की युवा आवाजों ने भारतीय लोकतंत्र के सामने कई नए प्रश्न खड़े किए हैं। आंदोलन को लेकर समाज में दो मत हो सकते हैं, आंदोलन की शैली, नेतृत्व और उसके राजनीतिक इस्तेमाल पर भी बहस हो सकती है,लेकिन एक बुनियादी सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने,असहमति व्यक्त करने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का युवाओं और विशेषकर जेन-जी को लेकर दिया गया दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने साफ कहा कि नई पीढ़ी सवाल करती है,तर्कसंगत उत्तर चाहती है,उसे केवल आदेश देकर नहीं समझाया जा सकता। उनके अनुसार आज जरूरत 'डिक्टेशन' की नहीं,'डिस्कशन' की और आदेश की नहीं,सहमति की है। भागवत ने हाल में इससे भी आगे बढ़कर कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध माध्यम है और जेन-जी के आंदोलन में उठाई गई शिकायतें जायज हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी कह देना उचित नहीं है। उनका मानना है कि आंदोलन का उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना नहीं,बल्कि सहमति और समाधान की दिशा में आगे बढ़ना होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत और छात्रों की नाराजगी के बीच संबंध की ओर भी उन्होंने संकेत किया।

भागवत के इस दृष्टिकोण की सराहना इसलिए भी की जानी चाहिए कि यह केवल किसी एक आंदोलन या किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र की उस मूल आत्मा को स्पर्श करता है,जिसमें सत्ता जनता से शक्ति प्राप्त करती है और जनता की आवाज सुनना उसकी संवैधानिक तथा नैतिक जिम्मेदारी है। विरोध को हमेशा विद्रोह मान लेना लोकतंत्र की समझ को संकुचित करना है। असहमति को राष्ट्रविरोध समझना उससे भी बड़ी भूल है। देश किसी एक विचार से बड़ा है और लोकतंत्र सत्ता से बड़ा। जो नागरिक देश के भविष्य को लेकर सवाल उठाता है, वह जरूरी नहीं कि देश का विरोध कर रहा हो,कई बार वह देश को बेहतर बनाने की बेचैनी व्यक्त कर रहा होता है। आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर जब हम स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं,तब हमें यह भी पूछना चाहिए कि हमारी आजादी का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या आजादी केवल तिरंगा फहराने,राष्ट्रगान गाने और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तक सीमित है? या इसका अर्थ यह भी है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर सवाल कर सके,व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कर सके और अपनी बात बिना भय के रख सके? यदि हम सचमुच विकसित भारत,समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत का सपना देखते हैं तो हमें भारत के युवाओं के सपनों को सुनना ही होगा।

भारत के महान चिंतकों ने युवाशक्ति को राष्ट्रनिर्माण का आधार माना है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को जागने,अपनी शक्ति पहचानने और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया था। उनके चिंतन का मूल संदेश यही था कि युवा केवल राष्ट्र का भविष्य नहीं,वर्तमान की सक्रिय शक्ति

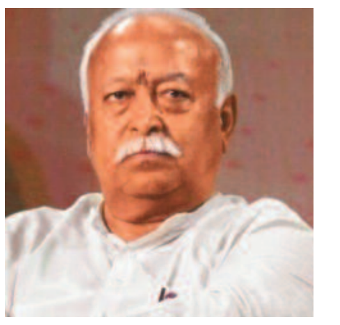

भी हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि परिवर्तन केवल सत्ता के गलियारों से नहीं आता,वह जागरूक नागरिकों की चेतना से आता है। डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने बार-बार युवाओं के सपनों को भारत के भविष्य से जोड़ा। उनके लिए सपना वह नहीं था जो सोते समय दिखाई देता है, बल्कि वह था जो व्यक्ति को सोने नहीं देता। आज के युवाओं की बेचैनी को इसी दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी और पिछली पीढ़ी के बीच अंतर स्वाभाविक है। पहले परिवार, विद्यालय और समाज में 'क्यों' पूछने की गुंजाइश कम थी,बड़े जो कहते थे,उसे मान लेना संस्कार समझा जाता था। आज का युवा प्रश्न करता है-क्यों,कैसे और किस लिए? वह केवल परंपरा के नाम पर किसी बात को स्वीकार नहीं करता। वह प्रमाण चाहता है,तर्क चाहता है और परिणाम देखना चाहता है। यह बदलाव चुनौती भी है और अवसर भी। यदि हम इस प्रश्नाकुलता को दबाएंगे तो कुंठा पैदा होगी,यदि इसे सही दिशा देंगे तो यही प्रश्न नवाचार, अनुसंधान और राष्ट्रनिर्माण की शक्ति बनेंगे।

विचारों के टकराव से घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति स्वयं 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः'की संवाद परंपरा से विकसित हुई है। उपनिषदों में प्रश्न हैं,उत्तर हैं,पुनः प्रश्न हैं। भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि हमें सिखाती है कि सत्य को एकांगी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। एक ही विषय के अनेक पक्ष हो सकते हैं। इसलिए बहस लोकतंत्र की कमजोरी नहीं,उसकी बौद्धिक ताकत है। समस्या बहस में नहीं,बहस के हिंसक हो जाने में है,समस्या असहमति में नहीं, असहमति के नाम पर अराजकता में है। इसीलिए भागवत की बात का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है-विरोध संविधान की मर्यादा में हो,शांतिपूर्ण हो और उसका लक्ष्य व्यक्ति को अपमानित करना नहीं,व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाना हो। आंदोलन लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक अनुशासन के साथ। सरकार की आलोचना लोकतंत्र है, हिंसा लोकतंत्र नहीं। प्रश्न करना स्वतंत्रता है,सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वतंत्रता नहीं। इसलिए सरकार और आंदोलनकारी-दोनों की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी अधिक बड़ी है,क्योंकि उसके पास सत्ता, प्रशासन और संस्थागत शक्ति होती है। किसी छात्र की आवाज को लाठी से दबाया जा सकता है,लेकिन उसकी आशंका को लाठी से समाप्त नहीं किया जा सकता। किसी आंदोलनकारी को राष्ट्रविरोधी कह देने से उसका प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता। यदि उसकी मांग गलत है तो तथ्य और तर्क से उसे गलत सिद्ध किया जाए। यदि मांग सही है तो उसे स्वीकार करने में संकोच क्यों? लोकतंत्र में सरकार का सबसे प्रभावी हथियार पुलिस नहीं,संवाद है।

यहां मोहन भागवत की भूमिका एक मार्गदर्शक की तरह दिखाई देती है। उन्होंने अनेक अवसरों पर केवल प्रशंसा करने के बजाय व्यापक सामाजिक हित के प्रश्न उठाए हैं। जब सत्ता या व्यवस्था किसी दिशा में आवश्यकता से अधिक आगे बढ़ती दिखाई देती है,तब एक जिम्मेदार मार्गदर्शक का दायित्व होता है कि वह उसे आत्ममंथन की ओर ले जाए। भागवत की यह भूमिका हमें महाभारत के भीष्म पितामह की याद दिलाती है-ऐसे व्यक्ति की,जो सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी समय-समय पर धर्म,मर्यादा और व्यापक हित की याद दिलाता है। यह तुलना व्यक्ति-पूजा के लिए नहीं,बल्कि मार्ग दर्शक की भूमिका की व्याख्या के लिए है। सरकारें जब जनता की आवाज समय पर सुनती हैं तो आंदोलन समस्या बनने से पहले समाधान बन सकता है। लेकिन जब शिकायतें महीनों और वर्षों तक फाइलों में पड़ी रहती हैं,जब संवाद के रास्ते बंद होते जाते हैं और जब नागरिक को लगता है कि उसकी सुनवाई नहीं होगी,तब असंतोष सड़क पर आता है। फिर वही आंदोलन राजनीतिक दलों,अवसरवादी तत्वों और निहित स्वार्थों के लिए मैदान बन जाता है। परिणामतः मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और आंदोलन का चरित्र बदलने लगता है। यही वह स्थिति है जिससे लोकतंत्र को बचाना है।

नीट और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों ने भी यही संदेश दिया है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार और संस्थाओं को असाधारण संवेदनशीलता दिखानी होगी। परीक्षा केवल एक प्रश्नपत्र नहीं होती,वह लाखों परिवारों के वर्षों के परिश्रम,सपनों और आर्थिक-सामाजिक आकांक्षाओं से जुड़ी होती है। यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी मेहनत निष्पक्ष व्यवस्था में नहीं आंकी गई, तो उसका आक्रोश स्वाभाविक है।

शाह संसद में बयान देने को तैयार,लेकिन विपक्ष सुनने को नहीं राजी

संजय सक्सेना,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार संसद में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई सहित हर पहलू पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस मुद्दे पर जवाब देंगे,जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष से यह भी कहा है कि वह गृह मंत्री के संसद में बयान के दौरान सदन से भाग नहीं जायें। यह और बात है कि इसके बाद भी विपक्ष सदन में हंगामा करता रहा,जो बताता है कि विपक्ष के मुंह में कुछ और, मन में कुछ और चल रहा है। क्योंकि विपक्ष बात तो छात्रों पर पैलेट गन और लाठीचार्ज की कर रहा है, लेकिन उसके दिल में चंदा चोरी पर हिन्दुओं को बांटने की साजिश पनप रही है। वहीं लोकसभा में सीटें बढ़ाकर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के मोदी सरकार के प्रयास से भी विपक्ष को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसलिये वह लगातार कोशिश कर रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह बिल नहीं पास हो,इसलिये वह 2026 की जनगणना के अनुसार परिसीमन के नाम हंगामा खड़ा कर रहा है।दरअसल,छात्र आंदोलनों,प्रदर्शन कारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई और उसके बाद संसद में पैदा हुआ गतिरोध इन दिनों भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर संसद का माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। एक तरफ विपक्ष इसे सरकार की दमनकारी नीति बताते हुए आक्रामक रुख अपनाए हुए है,तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी दो टूक कह दिया है कि वह इस मुद्दे पर हरसंभव और विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह

तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक सरगर्मी को चरम पर पहुंचा दिया है,जहां हर दल अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की जुगत में लगा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पूरे मामले पर सरकार का पक्ष बेहद स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है। उन्होंने दो टूक कहा है कि सरकार सदन में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई से जुड़े हर एक पहलू पर खुली चर्चा करने से पीछे नहीं हट रही है। सरकार का यह रुख साफ करता है कि वह किसी भी मुद्दे से भागने के बजाय उस पर आमने-सामने की बहस चाहती है। रिजिजू ने यह भी भरोसा दिलाया कि विपक्ष की मुख्य मांग के अनुरूप देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद इस संवेदनशील मुद्दे पर संसद में आकर सरकार का आधिकारिक जवाब देंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसके बावजूद संसद की कार्यवाही का सुचारू रूप से चलना तो दूर,विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी रहना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सत्ता पक्ष की ओर से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब सरकार खुद गृह मंत्री के स्तर पर विस्तृत बयान और चर्चा के लिए तैयार है,तो फिर विपक्ष सदन में चर्चा की बजाय सिर्फ व्यवधान क्यों पैदा कर रहा है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें गृह मंत्री के बयान के दौरान सदन से भागना नहीं चाहिए,बल्कि पूरी गंभीरता के साथ बहस में हिस्सा लेना चाहिए। सरकार का यह मानना है कि विपक्ष के मुंह पर कुछ और है और मन में कुछ और चल रहा है। बयानों की सतह के नीचे छिपी असली राजनीतिक रणनीतियों को टटोला जाए तो यह साफ नजर आता है कि छात्र आंदोलन सिर्फ एक तात्कालिक मुद्दा है,जिसके आड़ में कई बड़े राजनीतिक एजेंडे साधे जा रहे हैं। विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज तथा पैलेट गन के इस्तेमाल पर देश को जवाब दें। लेकिन इसके बावजूद अभी तक गृह मंत्री की ओर से इस विशिष्ट विषय पर सदन के भीतर कोई औपचारिक बयान सामने क्यों नहीं आया है, इसके पीछे कई व्यावहारिक और रणनीतिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि संसद की एक तयशुदा कार्यप्रणाली और गरिमा होती है, जिसके तहत किसी भी गंभीर विषय पर बयान देने से पहले गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों,स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभागों से पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाता है। जब तक घटना से जुड़े सभी पुख्ता और आधिकारिक आंकड़े हाथ में न हों, तब तक देश के गृह मंत्री द्वारा सदन में अधूरा या जल्दबाजी में बयान देना उचित नहीं माना जाता है।

संघ का जेन जी से संवाद, बीजेपी को वैचारिक नसीहत

अजय कुमार,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

भारतीय राजनीति में क्या जेन जी के बीच एक ऐसा वैचारिक और सामाजिक बदलाव आकार ले रहा है, जिसे पारंपरिक राजनीतिक चश्मे से देखना अब संभव नहीं रह गया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत द्वारा एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि देश का वैचारिक नेतृत्व अब युवा वर्ग,विशेषकर जेन जी यानी इंटरनेट युग में पैदा हुई और पली-बढ़ी पीढ़ी को लेकर बेहद गंभीर है। स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद संघ के प्रचारकों द्वारा देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर जेन जी के साथ सीधे संवाद स्थापित करने की योजना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि संघ अपनी पारंपरिक कार्यशैली से बाहर निकलकर इस डिजिटल पीढ़ी की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा है। यह पीढ़ी किसी भी व्यवस्था को आंख मूंदकर स्वीकार करने के बजाय उसे तर्क, पारदर्शिता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कसौटी पर परखती है। ऐसे में संघ का यह कदम केवल एक सामान्य जनसंपर्क अभियान नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े वैचारिक संगठन द्वारा भविष्य की वैचारिक जमीन को बचाने और बुनने की एक सुनियोजित रणनीति है।

आज के दौर में जेन जी की सोच को समझना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण और आवश्यक हो गया है क्योंकि यह पीढ़ी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, वैश्विक सूचना प्रवाह और त्वरित संवाद के माहौल में बड़ी हुई है। इनके लिए राजनीतिक निष्ठाएं पारंपरिक या आनुवंशिक नहीं हैं, बल्कि ये मुद्दों,शासन की गुणवत्ता, रोजगार के अवसरों,व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय के पैमानों पर सरकारों का मूल्यांकन करती हैं। संघ और उससे जुड़े वैचारिक संगठनों को यह अहसास हो चला है कि यदि इस पीढ़ी की आकांक्षाओं,असहजताओं और सवालों को समय रहते नहीं समझा गया,तो वैचारिक मोर्चे पर एक बड़ी खाई पैदा हो सकती है। पुरानी व्यवस्थाओं और धार्मिक-सामाजिक मान्यताओं को तार्किक कसौटी पर कसने की इस प्रवृत्ति ने राजनीतिक दलों के पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूलों को भी चुनौती दी है। जब संघ के प्रचारक देश के युवाओं के बीच जाएंगे,तो उनका मुख्य उद्देश्य यह जानना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों,आर्थिक प्राथमिकताओं और शासन प्रणाली को लेकर इस वर्ग के मन में क्या कसैलापन या असंतोष है। इस संवाद से मिलने वाला फीडबैक केवल संघ के सांगठनिक विस्तार का आधार नहीं बनेगा,बल्कि यह आने वाले समय में देश की सामाजिक और युवा रणनीति को नए सिरे से आकार देने का मुख्य दस्तावेज भी साबित होगा।

इस पूरी कवायद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की भूमिका और उसकी राजनीतिक कार्यप्रणाली भी केंद्र में है। पिछले एक दशक से अधिक समय से केंद्र की सत्ता पर काबिज और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर मुखर रहने वाली बीजेपी के लिए युवा वर्ग का समर्थन उसकी चुनावी सफलताओं की रीढ़ रहा है। हालांकि,जैसे-जैसे जेन जी मतदाता सूची में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है,वैसे-वैसे उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। यह पीढ़ी नारों और भावनात्मक बहसों से ज्यादा सुशासन,डिजिटल अर्थव्यवस्था,पर्यावरण,पारदर्शिता,अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और करिअर की अनिश्चितताओं जैसे मुद्दों पर बात करना चाहती है। ऐसे में यह सवाल बेहद प्रासंगिक हो जाता है कि क्या संघ के इस सीधे संवाद कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी को भी कोई वैचारिक या नीतिगत नसीहत दी जा सकती है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संघ का यह कदम अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के लिए एक आत्ममंथन का संदेश भी हो सकता है। संघ हमेशा से सरकार और समाज के बीच एक सेतु की तरह काम करता रहा है। यदि जमीनी संवाद के दौरान युवाओं की ओर से शासन की कार्यशैली,नौकरशाही की लालफीताशाही,रोजगार के संकट या वैचारिक असहिष्णुता को लेकर कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने आती है, तो संघ उसे पूरी गंभीरता से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगा।

संघ की जेन जी को लेकर दूरगामी रणनीति केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने तक सीमित नहीं है,बल्कि यह वैचारिक निरंतरता बनाए रखने की एक लंबी लड़ाई है। किसी भी संगठन के लिए यह स्वीकार करना सबसे कठिन होता है कि उसकी पुरानी वैचारिक भाषा नई पीढ़ी तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। संघ यह भली-भांति समझता है कि यदि आज के युवाओं से संवाद का सिलसिला नहीं जोड़ा गया,तो आने वाले दशकों में वैचारिक शून्यता पैदा हो सकती है,जिसका नुकसान राष्ट्रवाद के पूरे विमर्श को उठाना पड़ सकता है। इसलिए, यह संवाद कार्यक्रम इस बात की ताकीद करता है कि वैचारिक संगठनों को भी अपने तौर-तरीकों में लचीलापन लाना होगा। वे युवाओं को उपदेश देने के बजाय उनकी बात सुनने की मुद्रा में आ रहे हैं,जो एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। इसके जरिए संघ अपनी छवि को केवल एक अनुशासित और पारंपरिक संगठन के रूप में पेश करने के बजाय एक ऐसी जीवंत संस्था के रूप में स्थापित करना चाहता है जो समकालीन समय की हर जटिलता और युवा वर्ग की हर बेचैनी को समझने का माद्दा रखती है। कुल मिलाकर जेन जी के साथ संघ का यह सीधा संवाद भारतीय लोकतंत्र और राजनीति दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है। यदि संघ अपने प्रचारकों के माध्यम से युवाओं के वास्तविक फीडबैक को स्वीकार करने और उस पर अमल करने में सफल होता है,तो इससे न केवल समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण की तीक्ष्णता कम होगी, बल्कि शासन व्यवस्था में सुधार के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे।

इलाज के बाद बची बीमारी : अस्पतालों के नीचे दफन होता भविष्य

प्रो.रितेश कुमार जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

कूड़े का कोई टुकड़ा सिर्फ कूड़ा नहीं,खासकर जब वह अस्पताल से निकला हो। उसे जमीन में दबाने से खतरा खत्म नहीं होता,वह मिट्टी और पानी के रास्ते इंसानी जिंदगी तक पहुंच सकता है। मेडिकल कचरे के गलत निपटान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की सख्ती ने स्वास्थ्य व्यवस्था की अनदेखी उजागर की है। सत्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 9,178 स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच में केवल 5,715 नियमों के अनुरूप मिलीं। बाकी में भूजल सुरक्षा की अनदेखी, जरूरी अनुमति का अभाव, गलत जगह गड्ढे और जानवरों की पहुंच रोकने में लापरवाही मिली। जिस अस्पताल में बीमारी का इलाज होता है,वहीं संक्रमित कचरे का गलत निपटान इलाज और प्रदूषण की सीमा मिटा देता है। सवाल सिर्फ कचरे का नहीं, मिट्टी, पानी और उन परिवारों की जिंदगी का है, जो इसकी कीमत चुका सकते हैं।

एक साफ अस्पताल के बाहर गंदा सच क्यों खड़ा है?
जो इलाज देता है,वही अगर जहर बोए तो किस पर भरोसा करें?

धरती के गर्भ में दबा कचरा आंखों से ओझल हो सकता है,असर नहीं। संक्रमित कचरा भूजल तक न पहुंचे,इसलिए गहरे गड्ढे में दफन की प्रक्रिया के नियम कड़े हैं। जहां साझा जैव-चिकित्सा कचरा उपचार सुविधा नहीं है,वहां दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तय शर्तों पर गहरे गड्ढे में दफन की अनुमति है। गड्ढे जलस्रोतों और आबादी से सुरक्षित दूरी पर हों, भूजल स्तर गड्ढे के निचले हिस्से से कम से कम छह मीटर नीचे हो,कचरे को मिट्टी और चूने से ढकना तथा जानवरों की पहुंच रोकना जरूरी है। लेकिन नियमों की ताकत उनके पालन में है। सुविधा के नाम पर छोटी-सी लापरवाही प्रकृति के लिए वर्षों का संकट बन सकती है।

जब आंकड़े जमीन पर उतरते हैं,वे सिर्फ संख्या नहीं रहते, किसी की जिंदगी का खतरा बन जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में 477 सुविधाओं में भूजल सुरक्षा उल्लंघन मिले। 341 के पास जरूरी अनुमति नहीं थी और 316 में स्थल चयन तय मानकों के अनुरूप नहीं मिला। 253 जगह अभिलेख रखने में लापरवाही,229 स्थानों पर जानवरों की पहुंच रोकने की व्यवस्था नहीं थी और 216 जगह कचरे को पर्याप्त मिट्टी से ढकने में कमी मिली। उत्तर प्रदेश की 111 और राजस्थान की 33 स्वास्थ्य सुविधाओं में पूर्ण गैर-अनुपालन दर्ज हुआ। इन आंकड़ों को गांव के नक्शे पर रखें तो तस्वीर बदल जाती है। कहीं वह कुआं हो सकता है,जहां से परिवार पानी भरता है; कहीं वह खेत,जहां अगली फसल बोई जानी है।

खतरा अस्पताल से निकलते ही खत्म नहीं होता, कई बार कचरे के साथ शुरू होता है। चिंता केवल नियम टूटने की नहीं,बल्कि नियम टूटने पर भी व्यवस्था चलते रहने की है। चिकित्सकीय कचरे का खतरा मात्रा से अधिक उसकी प्रकृति में है। संक्रमित सामग्री,शरीर के अवशेष और रक्त या जैविक द्रव से सनी वस्तुओं का सुरक्षित उपचार जरूरी है। ऐसे कचरे तक पशु पहुंचें या भूजल से संपर्क हो,तो संक्रमण अस्पताल से बाहर फैल सकता है। इसलिए चिकित्सकीय कचरा केवल पर्यावरण मंत्रालय या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रश्न है। अस्पताल की स्वच्छता शल्य कक्ष में नहीं,कचरे के अंतिम पड़ाव पर परखी जाती है।

दुर्गम पहाड़ और लंबी दूरियां कठिनाई हो सकती हैं, जिम्मेदारी से मुक्ति का कारण नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों,हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड,जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दुर्गम भूभाग,कम आबादी और परिवहन कठिनाइयां साझा उपचार संयंत्रों की पहुंच सीमित करती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दस्तावेजों में ऐसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख है, जहां साझा जैव-चिकित्सा कचरा उपचार सुविधाएं पूरी नहीं हैं और दूरस्थ स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय उपचार, जिसमें गहरे गड्ढे में दफन शामिल है,पर निर्भर हैं। कुछ क्षेत्रों में साझा उपचार संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। मगर समाधान दूरस्थ क्षेत्रों को नियमों से मुक्त करना नहीं, वहां नियमों के पालन की तकनीकी और आर्थिक क्षमता पहुंचाना है।

अब सवाल आदेश जारी होने का नहीं,आठ सप्ताह में बदलाव दिखने का है। एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जैव-चिकित्सा कचरा निपटान के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पालन न होने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत कठोर निर्देश दिए जा सकते हैं और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है। लेकिन अदालत की समयसीमा को नई रिपोर्ट बनाने की अवधि बना देना इस संकट के साथ अन्याय होगा। हर उल्लंघनकारी सुविधा की दोबारा जांच हो,जिम्मेदारी तय हो, पुराने दफन गड्ढों का लेखा बने,भूजल जांच हो और सुधार का स्वतंत्र सत्यापन किया जाए। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कागजी निरीक्षण से आगे बढ़कर सुनिश्चित करना होगा कि जिसे 'अनुपालन' बताया जा रहा है,वहां जमीन भी वही सच बयान करे।

किसी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी सुविधा की कीमत किसे चुकाने देता है। हम ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बना सकते जो मरीज को बचाकर उसके आसपास की मिट्टी और पानी को खतरे में डाल दे। राज्यों को नियमित निरीक्षण,प्रशिक्षित कर्मचारी,पारदर्शी अभिलेख, आधुनिक उपचार सुविधाएं और साझा जैव-चिकित्सा कचरा उपचार केंद्रों का विस्तार करना होगा। जहां गहरे गड्ढे में दफन करना अपरिहार्य है, वहां हर शर्त अक्षरशः लागू हो;जहां साझा उपचार केंद्र उपलब्ध है,वहां जोखिमपूर्ण कचरे को गड्ढे में दफन करने की गुंजाइश ही क्यों रहे? धरती तुरंत शिकायत नहीं करती,पानी भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराता। लेकिन प्रदूषण का हिसाब पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए अब चिकित्सकीय कचरे को छिपाना नहीं,उसकी पूरी यात्रा को जवाबदेह बनाना होगा–अस्पताल के द्वार से अंतिम उपचार तक। क्योंकि बीमारी से लड़ने वाला अस्पताल यदि अपनी ही छाया में बीमारी दफना रहा है, तो सवाल सिर्फ गड्ढे की गहराई का नहीं,हमारी जिम्मेदारी की गहराई का है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

मौत के 42 दिन बाद आया आयुष्मान का मैसेज 'आप स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं'

जशपुर के आरक्षक की 30 जून को हो चुकी थी मौत,आयुष्मान रिकॉर्ड में 42 दिन तक अस्पताल में भर्ती दिखाया गया,पत्नी ने लापरवाही के जिम्मेदारों पर की कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में इलाज के लिए जशपुर जिले के एक आरक्षक को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत 30 जून को हो चुकी थी। लेकिन आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड में उसे 42 दिन तक अस्पताल में भर्ती दिखाया गया। 42 दिन बाद उसके मोबाइल पर आयुष्मान सारथी की ओर से मैसेज आया कि वह स्वस्थ होकर घर लौट रहा है। जबकि आरक्षक का मृत्यु प्रमाण-पत्र भी जारी हो गया है।

जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के कांसाबेल निवासी आरक्षक देवनारायण राम को 26 जून को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 30 जून को उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मृत्यु प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिया। इसके बावजूद आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड में उसे अस्पताल में भर्ती बताया गया। मृतक की पत्नी सीमा कुजूर,जो जिला

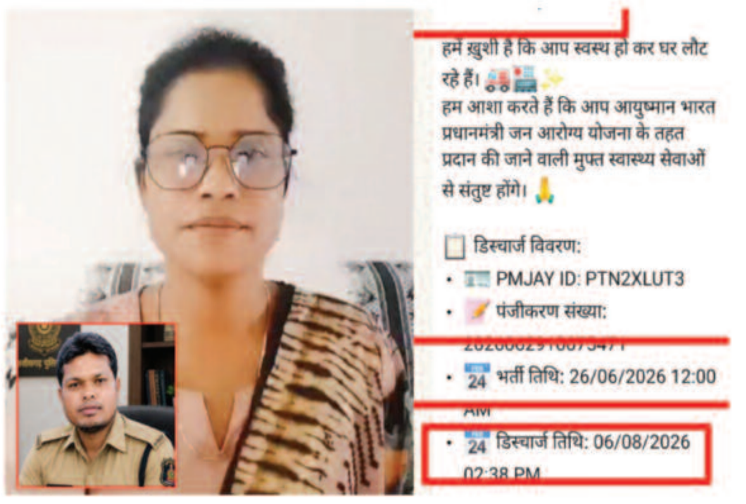

अस्पताल जशपुर में स्टाफ नर्स है,उसने बताया कि पति की मौत के करीब 42 दिन बाद उनके मोबाइल पर आयुष्मान सारथी की ओर से संदेश आया। इसमें लिखा था-'प्रिय देवनारायण,हमें खुशी है कि आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं।' संदेश मिलने के बाद परिवार हैरान रह गया। सीमा कुजूर ने सवाल उठाया कि यह महज तकनीकी त्रुटि है या आयुष्मान योजना के रिकॉर्ड में कोई गंभीर गड़बड़ी हुई है,इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी उसे 42 दिन तक अस्पताल में भर्ती और जीवित दिखाना गंभीर मामला है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जांच का विषय है मामला

मृतक की पत्नी का कहना है कि इस तरह का संदेश परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि गरीब और आम लोगों का स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा बना रहे,इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई जरूरी है। यह ऑटो जेनेरेटेड मैसेज है। हमारे यहां से नहीं गया है। 30 जून को ही मरीज का आयुष्मान कार्ड ब्लॉक कर दिया गया था। मरीज आईसीयू में भर्ती था, 5 दिन का ही बिल उसके कार्ड से कटा है। इस तरह के मैसेज मिलना किसी भी परिवार के लिए भी ठीक नहीं है। मैं रायपुर स्थित संबंधित विभाग को लेटर लिखूंगा।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री रामविचार नेताम होंगे शामिल

15 अगस्त की तैयारियों का कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण,व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों का कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन और पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम शामिल होंगे। समारोह को गरिमामय एवं व्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर अजीत वसंत ने कार्यक्रम स्थल पर मंच व्यवस्था, मार्च पास्ट की तैयारी, बैठक व्यवस्था, साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत, सुरक्षा एवं यातायात सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित समय से पहले दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था एवं आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने तथा समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए।

हर घर तिरंगा अभियान को लेकर समलाया मंडल की बैठक संपन्न

शक्तिकेंद्रों को वितरित किए गए तिरंगा झंडे,तिरंगा यात्रा को सफल बनाने कार्यकर्ताओं से किया आह्वान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
भारतीय जनता पार्टी सरगुजा जिला के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को लेकर समलाया मंडल की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर समलाया मंडल के प्रत्येक शक्तिकेंद्र को तिरंगा झंडों के बंडल वितरित किए गए, जिन्हें बूथ कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के सहयोग से घर-घर पहुंचाकर तिरंगा फहराया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल सिंह मेजर ने कहा कि तिरंगा हमारी आन,बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण अवसर है। सभी कार्यकर्ता इसे अभियान के रूप में लेकर प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाएं। भाजपा सरगुजा जिला ध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को मजबूत करना है। कार्यकर्ता समाज के प्रत्येक वर्ग को अभियान से जोड़ते हुए तिरंगा यात्रा को भी व्यापक और सफल बनाएं। मंडल प्रभारी डॉ. अंबिकेश केशरी ने कहा कि प्रत्येक शक्तिकेंद्र और बूथ स्तर तक अभियान की प्रभावी तैयारी सुनिश्चित की जाए। कार्यकर्ता घर-घर संपर्क कर लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें तथा तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला महामंत्री अरुणा सिंह,निश्चल प्रताप सिंह,रूपेश दुबे, अभिषेक शर्मा, अवधेश सोनकर, अभिषेक सिंह देव, अजय सोनी, सर्वेश तिवारी, श्रीमती शालिनी सिंह, शैलेंद्र शर्मा, आलोक दास सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कुलपति आवास पर अभाविप के सवाल,विश्वविद्यालय ने कहा...परिसर का आवास अनुकूल नहीं...

सुरक्षा-सफाई के खर्च को लेकर भी उठे सवाल,कुलसचिव बोले...यह किसी एक माह का बिल नहीं,आरोप तथ्यहीन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में वित्तीय खर्च और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। अभाविप ने कुलपति आवास,फर्नीचर खरीदी,सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर खर्च को लेकर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की थी। वहीं विश्व विद्यालय के कुलसचिव एसपी त्रिपाठी ने कहा कि कुलपति का शहर में भी आवास है और विश्वविद्यालय परिसर में बना आवास उनके अनुकूल नहीं होने के कारण वहां रहना संभव नहीं है। अभाविप ने आरोप लगाया था कि करीब एक करोड़ रुपए की लागत से कुलपति भवन का निर्माण होने के बावजूद कुलपति किराए के भवन में रह रहे हैं। परिषद ने इसे विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त आर्थिक भार बताते हुए खर्च और निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक करने की मांग की थी। इस पर कुलसचिव ने कहा कि परिसर में बने आवास की उपयोगिता और अनुकूलता को देखते हुए

ही निवास का निर्णय लिया जाता है। उनका कहना है कि कुलपति के शहर में भी आवास होने की जानकारी उन्हें मिली है।

सुरक्षा-सफाई के खर्च पर भी जवाब : अभाविप ने विश्वविद्यालय में सुरक्षा के नाम पर करीब 9.62 लाख रुपए और सफाई व्यवस्था पर 1.89 लाख रुपए खर्च किए जाने पर सवाल उठाए थे। परिषद ने इन खर्चों की आवश्यकता और औचित्य की जांच की मांग की है। इस पर कुलसचिव एसपी त्रिपाठी ने कहा कि इन खर्चों को किसी एक माह का बिल बताकर भ्रष्टाचार से जोडऩा सही नहीं है। 'यह किसी एक महीने का बिल नहीं है। सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर होने वाले खर्च को पूरे संदर्भ में देखा जाना चाहिए।' उन्होंने सुरक्षा व सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया।

फर्नीचर और टेंडर पर भी उठे सवाल

अभाविप ने विश्वविद्यालय के मद से करीब 22 लाख रुपए के सोफा और फर्नीचर खरीदे जाने तथा अन्य सामान के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए हैं। परिषद ने बिल,अनुमति और उपयोग का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके अलावा कुछ टेंडरों में एल-1 की जगह एल-2 निविदाकार को काम दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है। इन आरोपों पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से दस्तावेजों और संबंधित प्रक्रियाओं के आधार पर स्थिति स्पष्ट किया जाना बाकी है।

शुल्क वृद्धि को लेकर विद्यार्थियों में नाराजगी

अभाविप ने छात्र कल्याण शुल्क, पीएचडी शुल्क सहित विभिन्न शुल्कों में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया है। परिषद का कहना है कि शुल्क बढ़ने के बावजूद विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन से इन सभी बिंदुओं पर तथ्यात्मक जवाब और खर्च का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

नवप्रवेशी छात्रों को बताया सफलता का मंत्र,कहा... अनुशासन और सकारात्मक सोच से मिलेगी मंजिल

महाविद्यालय में इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित,अतिथियों ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक,कौशल और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रहने किया प्रेरित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के वार्षिक कैलेंडर-2026 के अनुसार महाविद्यालय में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन (दीक्षारंभ) कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीए,बीएससी, बीकॉम, बीसीए और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का चंदन-टीका लगाकर स्वागत किया गया और मिष्ठान वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक संस्थान है और विद्यार्थी इसकी 66वीं पीढ़ी का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखना सभी

की जिम्मेदारी है। आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में बेहतर तकनीकी एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि एवं महाविद्यालय के पूर्व छात्र,वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट हरिशंकर जायसवाल ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में प्रवेश विद्यार्थियों के जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है। विद्यालय से महाविद्यालय तक का सफर केवल कक्षा बदलने का नहीं, बल्कि सोच, व्यक्तित्व और जीवन-दृष्टि के विस्तार का अवसर है। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुशासन,समयपालन, ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। प्राचार्य प्रो. अनिल सिन्हा ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की शैक्षणिक परंपराओं, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित कक्षाओं में उपस्थित रहने,पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करने तथा खेल,सांस्कृतिक गतिविधियों, एनएसएस और एनसीसी में सक्रिय सहभागिता करने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. राजकमल मिश्रा ने नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बहुविषयक शिक्षा,कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसरों के साथ विद्यार्थियों को रुचि व क्षमता के अनुसार विषय चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी। कार्यक्रम में परीक्षा नियंत्रक डॉ. एमके मौर्य, डॉ. कामिनी,विनीत गुप्ता,एसके केरकेट्टा,क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मिलिंद सिंह, एनसीसी अधिकारी पंकज अहिरवार,गिरिजा सिंह, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी राजीव कुमार,दीपिका स्वर्णकार,लाइब्रेरियन चमन कुमार सहित विभिन्न गतिविधियों के प्रभारी प्राध्यापक उपस्थित रहे।

डॉ. आरसी आर्या, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक

नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दबाने 8 लाख का सौदा, 7 नामजद समेत अन्य पर केस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
कोतवाली थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए समझौते का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने और आरोपी से समझौता कराने की कोशिश के आरोप में पंचनामा में हस्ताक्षर करने वाले सात लोगों समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि पीड़ित परिवार को आरोपी से 8 लाख रुपए दिलाने का प्रस्ताव दिया गया था। जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा 20 जुलाई को उप सरपंच के घर काम करने गई थी। वह वहां घरेलू काम और खाना बनाने का काम करती थी। आरोप है कि इसी दौरान उप सरपंच के पति तरुण जायसवाल ने उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजन को दी। मामला सामने आने के बाद आरोपी पक्ष की ओर से समझौते का प्रयास किए जाने का आरोप है। 21 जुलाई को पीड़िता के पिता को 8 लाख रुपए देने का प्रस्ताव दिया गया और इस संबंध में पंचनामा तैयार कराया गया। इसमें 4 लाख रुपए तत्काल तथा शेष 4 लाख रुपए फरवरी 2027 में धान बेचने के बाद देने का उल्लेख बताया गया है। पंचनामा में सात लोगों के हस्ताक्षर भी हैं। परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।

रिपोर्ट के बाद फरार हुआ आरोपी, बिहार से गिरफ्तार : पीड़िता ने 22 जुलाई को कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने तलाश के बाद उसे 6 अगस्त को पटना, बिहार से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।

पुलिस ने पीड़ित परिवार पर केस दर्ज नहीं कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप में विवेक पैकरा,अशोक जायसवाल,सरजू तिर्की,नान साय, नोहर साय,किशुन राम और जगजीवन राम समेत अन्य के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धारा 21(2),249(बी) और 351(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

रोशनदान से प्रवेश किए चोर ने बाइक मोबाइल और नकद रकम पार किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
कोतवाली थाना क्षेत्र में किचन के रोशनदान से प्रवेश किए चोर ने मोटरसायकल, नकद रकम और मोबाइल फोन चोरी कर लिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज करके विवेचना में लिया है। महामायापारा अंबिकापुर निवासी मोनिका विश्वकर्मा पति विनोद विश्वकर्मा ने कोतवाली पुलिस को बताया है कि, 22 जुलाई की रात को करीब 10 बजे वे सपरिवार खाना खाकर सो

रहे थे। सुबह उठने पर पता चला कि उनके पति का मोबाइल फोन बिस्तर के पास से गायब है। घर में खोजबीन करने पर मोबाइल का पता नहीं चला। घर के हाल में रखा लेडिज पर्स फेंका हुआ था, और पर्स में रखा 3000 रुपये नहीं था। परछी में पल्सर मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 डीएच 1634 भी नहीं था। रिपोर्ट पर पुलिस अग्रिम जांच, कार्रवाई कर रही है।

राष्ट्रीय एकता जागरूकता का संदेश लेकर स्कूली बच्चों ने निकाली साइक्लोथॉन

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लगभग 200 विद्यार्थियों ने लिया उत्साहपूर्वक हिस्सा

-संवाददाता-
बलरामपुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर-रामानुजगंज वैभव बैंकर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी की उपस्थिति में जिला पुलिस द्वारा साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइक्लोथॉन का आयोजन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड बलरामपुर से हाई स्कूल खेल मैदान बलरामपुर तक किया गया। कार्यक्रम में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर,स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम बलरामपुर तथा सरस्वती शिशु मंदिर बलरामपुर के लगभग 200 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बलरामपुर विश्व दीपक त्रिपाठी द्वारा हरी झंडी दिखाकर साइक्लोथॉन को रवाना कर किया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से प्रारंभ हुई साइक्लोथॉन निर्धारित मार्ग से होते हुए हाई स्कूल खेल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। साइक्लोथॉन में शामिल विद्यार्थियों ने एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ साइकिलिंग करते हुए राष्ट्रीय एकता, भाईचारे एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश आमजन तक पहुंचाया। विद्यार्थियों ने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने,पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने तथा समाज में एकता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी, रक्षित निरीक्षक एवं यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन,कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर के प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद बालक हिंदी एवं अंग्रेजीमाध्यम विद्यालय बलरामपुर के प्राचार्य,सरस्वती शिशु मंदिर बलरामपुर के प्राचार्य सहित पुलिस अधिकारी-कर्मचारी एवं विद्यालयीन शिक्षक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन में राष्ट्रीय एकता,पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली एवं सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना रहा। साइक्लोथॉन में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता ने कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाया।

स्व. रविंद्र तिवारी की पंचम पुण्यतिथि पर पंडो बच्चों के बीच हुआ न्योता भोज

श्रद्धांजलि के साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण,बच्चों को कॉपी व शैक्षणिक किट का वितरण

-संवाददाता-
पटना/कोरिया,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
पूर्व महोरा जमींदार एवं शिक्षक हितों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले स्वर्गीय रविंद्र तिवारी की पंचम पुण्यतिथि पर उनके गृहग्राम महोरा के सुदूर अंचल जामझरिया स्थित विद्यालय में पंडो जनजाति के बच्चों के बीच श्रद्धांजलि स्वरूप न्योता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र कुमार गुप्ता एवं सहायक संचालक कौशिक भद्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही, कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय रविंद्र तिवारी के सामाजिक एवं शैक्षणिक योगदान को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, आयोजन का उद्देश्य उनकी स्मृति को केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रखते हुए शिक्षा, पर्यावरण और समाजसेवा से जोड़ना रहा।

'एक पेड़ मां के नाम' के तहत हुआ पौधरोपण-पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम'अभियान के तहत पौधरोपण किया गया,उपस्थित अधिकारियों,शिक्षकों एवं अन्य लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया,इस दौरान बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए पौधों की देखभाल और संरक्षण के महत्व की जानकारी दी गई,इसके साथ ही विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को कॉपी एवं शैक्षणिक किट का वितरण किया गया,पंडो जनजाति के बच्चों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम से शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहयोग का संदेश भी दिया गया।

करीब दो दशक तक शिक्षकों के अधिकारों के लिए किया संघर्ष

स्वर्गीय रविंद्र तिवारी के संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने वर्ष 1998 से शिक्षकों के अधिकार एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष किया, उनका संघर्ष ब्लॉक एवं जिला स्तर से आगे बढ़कर राज्य की राजधानी तक पहुंचा। लगभग दो दशक तक जारी इस संघर्ष के बाद वर्ष 2018 में उनकी मांगों से संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आया, शिक्षकों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाने के बाद उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को भी अपने संघर्ष का हिस्सा बनाया,इस दिशा में भी उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखे और शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय के लिए आवाज उठाई।

कई संगठनों में निभाई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

स्वर्गीय तिवारी को संघर्षशील,जुझारू और सहयोगी व्यक्तित्व के रूप में याद किया गया। सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही,उन्होंने छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के प्रांतीय सचिव,छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी संघ सरगुजा संभाग के संयोजक तथा ब्राह्मण समाज पटना मंडल के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया, इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने कर्मचारियों, शिक्षकों और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया,उनके सहयोगी और संघर्षशील स्वभाव के कारण संगठनात्मक क्षेत्र में भी उनकी अलग पहचान बनी रही।

आकस्मिक निधन के बावजूद संघर्ष की विरासत कायम

लगभग पांच वर्ष पूर्व स्वर्गीय रविंद्र तिवारी का आकस्मिक निधन हो गया, उनके निधन को उनके परिवार, साथियों और सामाजिक एवं कर्मचारी संगठनों के लिए अपूरणीय क्षति बताया गया,हालांकि,उनके साथ जुड़े लोगों का कहना है कि उनका संघर्ष, समर्पण और समाज के लिए किए गए कार्य आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की वास्तविक विरासत उसके जाने के बाद भी समाज में दिखाई देती है,शिक्षा,पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंद बच्चों के बीच सहयोग से जुड़ा यह आयोजन इसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

शिक्षकों एवं विद्यालय स्टाफ की रही सहभागिता

कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे, बच्चों के बीच न्योता भोज,शैक्षणिक सामग्री वितरण और पौधरोपण के कार्यक्रम ने पुण्यतिथि आयोजन को सामाजिक सरोकारों से जोड़ दिया,कार्यक्रम का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष रुपेश सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, उपस्थित जनसमूह ने स्वर्गीय रविंद्र तिवारी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष, समर्पण और योगदान को नमन किया।

जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था देवगढ़ रवाना

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा शहर,बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हुए शामिल

-संवाददाता-
सूरजपुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
सावन के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए सोमवार को सूरजपुर से कांवरियों का विशाल जत्था जमदग्नि महर्षि की तपोभूमि देवगढ़ के लिए रवाना हुआ। कांवरियों के जत्थे के रवाना होने के दौरान पूरा वातावरण भगवान भोलेनाथ के जयघोष से गूंज उठा। हर-हर महादेव, बोल बम के जयकारों के बीच श्रद्धालु उत्साह और भक्ति के साथ देवगढ़ के लिए रवाना हुए। इस धार्मिक यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला एवं पुरुष कांवरियों ने पूरे उत्साह के साथ कांवर लेकर यात्रा शुरू की। कई श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भगवान शिव के भजनों और जयकारों से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया।

कांवरियों ने पवित्र जल लेकर देवगढ़ पहुंचने और भगवान भोलेनाथ का विधिवत जलाभिषेक करने का संकल्प लिया। श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना और

जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इसी आस्था और विश्वास के साथ वे देवगढ़ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे तथा क्षेत्र एवं परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे।

रास्ते में जगह-जगह हुआ कांवरियों का स्वागत : सूरजपुर से देवगढ़ तक कांवरियों की सुविधा के लिए रास्ते में जगह-जगह समाजसेवियों और श्रद्धालुओं द्वारा जलपान एवं सेवा की व्यवस्था की गई। कांवरियों के लिए ठंडा पानी,शरबत,चाय, फल एवं अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई थी। सेवा शिविरों में लोगों ने उत्साहपूर्वक कांवरियों का स्वागत किया और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने भी कांवरियों का उत्साह बढ़ाया। जगह-जगह हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाए गए। सेवा में जुटे लोगों ने कहा कि कांवरियों की सेवा करना भगवान शिव की सेवा के समान है,इसलिए वे पूरी श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

भक्ति और आस्था में सराबोर हुआ माहौल

कांवर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। डीजे एवं भक्ति गीतों के साथ कांवरियों का जत्था आगे बढ़ता रहा। युवा वर्ग के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी पूरे उत्साह से यात्रा में शामिल हुए। सावन के महीने में देवगढ़ में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कांवरियों के जत्थे के रवाना होने से सूरजपुर शहर सहित पूरे मार्ग का वातावरण शिवमय हो गया। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए देवगढ़ की ओर बढ़े। देवगढ़ पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा पूर्ण करेंगे।

एंबुलेंस नहीं पहुंची तो मरीज को झलगी में 2 किमी ढोकर ले गए ग्रामीण

भईसापाठ में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल, बीमार को कंधों पर लेकर पैदल चलने मजबूर हुए ग्रामीण

-संवाददाता-
बलरामपुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र कुसमी के भईसापाठ गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति सामने आई है। गांव में एंबुलेंस नहीं पहुंच पाने के कारण बीमार मरीज को ग्रामीणों ने झलगी में रखकर करीब 2 किलोमीटर तक पैदल ढोया। ग्रामीणों के अनुसार मरीज की तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस बुलाने का प्रयास किया गया,लेकिन गांव तक वाहन नहीं पहुंच सका। इसके बाद ग्रामीणों ने मरीज को झलगी में रखा और कंधों पर उठाकर पैदल मुख्य सड़क तक ले गए। इस घटना ने वनांचल क्षेत्र में सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किए जा रहे सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक बेहतर सड़क और नियमित स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण आपात

स्थिति में मरीजों को काफी परेशानी होती है। एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों को ही मरीज को उठाकर ले जाना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से गांव तक सड़क और स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का सवाल-आखिर कब पहुंचेगा विकास? ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजनाओं और विकास के दावों के बावजूद वनांचल के गांवों में मूलभूत सुविधाएं अब भी चुनौती बनी हुई हैं। उनका सवाल है कि गंभीर स्थिति में मरीजों को कंधों पर ढोने की मजबूरी आखिर कब खत्म होगी।

हाईवे रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा...अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत

-संवाददाता-
लखनपुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
हाईवे रोड पर आज शाम लगभग 6:40 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बेलदगी निवासी रूप देव रजवाड़े की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रूप देव रजवाड़े अपनी निजी बाइक क्रमांक सीजे15 ईसी 7788 से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान लहपटरा स्थित हाईवे रोड पर किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रूप देव रजवाड़े ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर लखनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और

मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अज्ञात वाहन एवं उसके चालक की तलाश में जुटी हुई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक के परिजनों और क्षेत्रवासियों में शोक का माहौल है। पुलिस द्वारा दुर्घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

करैत के डसने से युवक की मौत,रात में जमीन पर सोते समय होंठ पर काटा

परिजन तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित किया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
जयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कंदरई में जहरीले सांप के डसने से 36 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना बीती रात करीब 2.30 बजे की बताई जा रही है। युवक घर में परिवार के साथ जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान करैत सांप ने उसके होंठ पर डस लिया। जानकारी के अनुसार कंदरई निवासी पूर नारायण बिंझिया (36) पिता बुधनाथ रात में परिवार के साथ घर में सो रहा था। इसी दौरान सांप ने उसके होंठ पर डस लिया। सांप के डसने की जानकारी मिलते ही परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बारिश में बढ़ जाता है सर्पदंश का खतरा

बारिश के मौसम में जहरीले सांपों के घरों और आबादी वाले क्षेत्रों में निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में ग्रामीणों से रात के समय जमीन पर सोने से बचने,घर के आसपास साफ-सफाई रखने और सांप के डसने की स्थिति में झाड़-फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचने की अपील की गई है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 अगस्त को जिले में बच्चों को खिलाई गई एल्बेंडाजोल की दवा

17 अगस्त को मॉपअप दिवस पर शेष बच्चों को खिलाई जाएगी दवा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 10 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत सरगुजा जिले में निर्धारित लक्ष्य 3 लाख 48 हजार 224 बच्चों को एल्बेंडाजोल की कृमिनाशक दवा खिलाई जानी थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से जिले के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य चिन्हांकित स्थानों पर अभियान का संचालन किया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षक एवं संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा समन्वित रूप से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। अभियान के दौरान बच्चों एवं अभिभावकों को कृमि संक्रमण से बचाव के उपायों के संबंध में भी जागरूक किया गया। बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने, नाखून साफ रखने, स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन करने तथा साफ पानी का सेवन करने के लिए प्रेरित किया गया।

बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण अभियान- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य, पोषण, शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास को बेहतर बनाना है। कृमि संक्रमण के कारण बच्चों में कमजोरी, खून की कमी, भूख में कमी तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी उद्देश्य से शासन द्वारा निर्धारित अवधि में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने का अभियान संचालित किया जाता है।

17 अगस्त को होगा मॉप-अप दिवस-

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जो बच्चे किसी कारणवश 10 अगस्त को एल्बेंडाजोल की दवा लेने से छूट गए हैं, उन्हें 17 अगस्त 2026 को आयोजित मॉप-अप दिवस के दौरान दवा खिलाई जाएगी। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र बच्चा कृमिनाशक दवा से वंचित न रहे।

वन विभाग की बड़ी कार्यवाही,चालक ट्रक छोड़कर हुए फरार

एक ट्रक अवैध खैर लकड़ी से लदा ट्रक जप्त,लकड़ी एवं ट्रक की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई

-संवाददाता-
बलरामपुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध कत्था (खैर लकड़ी) तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक खैर लकड़ी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक वाड्रफनगर से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर अवैध कत्था (खैर लकड़ी) लेकर जा रहा था। जप्त खैर लकड़ी एवं वाहन की अनुमानित कीमत 20 लाख रूपये बताई गई है। जानकारी के अनुसार, वन विभाग की टीम को अवैध तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश की। वन विभाग की कार्रवाई को देखते हुए ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर वन विभाग कार्यालय पहुंचाया है। ट्रक में लदे खैर लकड़ी 20 घन मीटर की बताई गई है विभाग की टीम के द्वारा उससे जुड़े

दस्तावेजों की जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक प्रारंभिक जांच में अवैध तस्करी की आशंका जताई जा रही है।

गौरवपथ से स्कूटी वाहन पार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।
लिफ्ट लेकर बैठे अज्ञात व्यक्ति को छोडने गए युवक का स्कूटी वाहन अज्ञात ने पार कर दिया। घटना नया बस स्टैण्ड गौरवपथ की है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के श्रीगढ़ गौटियापारा निवासी सतनारायण राजवाड़े ने पुलिस को बताया है कि, वह अपने पिता रामधन के नाम पर पंजीकृत स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी 15 डीटी 3581 को लेकर 30 जुलाई को शाम करीब 7.30 बजे अपने काम से बिलासपुर चैक गया था। यहां से वापस घर आते समय गंगासागर तलाब के पास एक व्यक्ति उससे लिफ्ट मांगा तो वह उसे छोड़ने के लिए नया बस स्टैण्ड गया था, और गौरवपथ में ही स्कूटी को खड़ा किया था, जिसमें चाबी लगा था। इसी बीच मौका देखकर अज्ञात व्यक्ति स्कूटी को चोरी करके ले गया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

CMYK

मुफ्त के पौधे खोलेंगे समृद्धि की राह : सोनहत में नीलगिरी क्लोन से चमकेगी किसानों की किस्मत

वन विभाग की पहल से निजी भूमि पर हरियाली के साथ तैयार होगा अतिरिक्त आय का जरिया,50 से 5000 तक नीलगिरी क्लोन पौधे निशुल्क देने की व्यवस्था

-राजन पाण्डेय-

सोनहत,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। वनांचल सोनहत में वर्षों से खाली अथवा ऐसी निजी भूमि,जहां पारंपरिक खेती करना किसानों के लिए कठिन है,अब आने वाले समय में आर्थिक समृद्धि का आधार बन सकती है,वन विभाग द्वारा किसानों और ग्रामीणों को निजी भूमि पर व्यावसायिक वृक्षारोपण के लिए उन्नत किस्म के नीलगिरी (यूकेलिप्टस) क्लोन पौधे निशुल्क उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है, मानसून के अनुकूल मौसम में शुरू हुई इस पहल के तहत पात्र आवेदकों को उनकी भूमि के अनुरूप 50 से लेकर 5000 तक पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल केवल पौधरोपण तक सीमित नहीं है,यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से पौधों का रोपण, नियमित देखभाल और भविष्य में बेहतर बाजार से जुड़ाव सुनिश्चित कर पाते हैं तो नीलगिरी का यह प्लांटेशन अगले कुछ वर्षों में उनकी 'हरित पूंजी' बन सकता है, हालांकि इससे होने वाली आय तत्काल नहीं होगी और वास्तविक कमाई पौधों की जीवित रहने की दर,भूमि की गुणवत्ता, प्रबंधन,कटाई की अवधि और बाजार भाव पर निर्भर करेगी।

50 से 5000 तक पौधे निशुल्क निजी भूमि का होगा सत्यापन

वन विभाग की योजना के तहत किसानों को उनकी उपलब्ध निजी भूमि के अनुसार नीलगिरी के क्लोन पौधे दिए जा रहे हैं, एक आवेदनकर्ता को न्यूनतम 50 से लेकर अधिकतम 5000 तक पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है,पूर्व में आवेदन करने वाले किसानों की भूमि का सत्यापन कर पौध वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है,वन परिक्षेत्राधिकारी सोनहत श्री राठिया के मार्गदर्शन में विभागीय अमला आवेदकों की भूमि का सत्यापन कर रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक निजी भूमि पर ही पौधरोपण किया जाए और पात्र किसानों तक योजना का लाभ पहुंचे, निशुल्क पौधे मिलने से किसानों को शुरुआत में पौध खरीदने का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि भूमि की तैयारी,गड्ढे तैयार करना,पौधरोपण, सिंचाई,निराई-गुड़ाई, सुरक्षा,रोग-कीट नियंत्रण, कटाई और परिवहन जैसी लागत किसानों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार वहन करनी पड़ सकती है।

नीलगिरी क्यों बन सकती है अतिरिक्त आय का साधन?

नीलगिरी तेजी से बढ़ने वाली वृक्ष प्रजातियों में शामिल है,इसकी लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से पल्प और पेपर उद्योग में किया जाता है,इसके अलावा पैकेजिंग,पैनल और कुछ अन्य औद्योगिक उपयोगों में भी इसकी मांग रहती है,यही वजह है कि ऐसी निजी भूमि,जहां नियमित कृषि करना मुश्किल है या जहां किसान अन्य लाभकारी फसलें नहीं ले पा रहे हैं,वहां परिस्थितियों के अनुकूल योजनाबद्ध नीलगिरी रोपण अतिरिक्त आय का विकल्प बन सकता है,लेकिन इसे पारंपरिक फसल की तरह नहीं समझना चाहिए। गेहूं,धान या सब्जी जैसी फसलों में जहां मौसम के अनुसार कुछ महीनों में आय मिल सकती है,वहीं नीलगिरी एक मध्यम अवधि का निवेश है, किसान को पौधरोपण के बाद कुछ वर्षों तक धैर्य और देखभाल की आवश्यकता होगी।

4 से 6 वर्ष में कटाई योग्य आकार तक पहुंचने की संभावना-नीलगिरी की कई व्यावसायिक किस्मों की खासियत उनकी तेज वृद्धि है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपयुक्त जलवायु, मिट्टी,क्लोन की गुणवत्ता, वर्षा,सिंचाई और वैज्ञानिक प्रबंधन के आधार पर कई व्यावसायिक प्लांटेशन लगभग 4 से 6 वर्ष के चक्र में कटाई योग्य आकार तक पहुंच सकते हैं,हालांकि यह कोई निश्चित अवधि नहीं है। प्रत्येक भूमि की स्थिति अलग होती है, जहां पर्याप्त नमी,उपयुक्त मिट्टी और बेहतर देखभाल उपलब्ध होगी, वहां पौधों की वृद्धि अपेक्षाकृत अच्छी हो सकती है,इसके विपरीत पानी की कमी,खराब भूमि,रोग या सुरक्षा की समस्या पौधों की वृद्धि और अंतिम उत्पादन को प्रभावित कर सकती है,इसलिए किसान के लिए यह समझना जरूरी है कि आज लगाया गया पौधा तत्काल कमाई नहीं देगा, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए संपत्ति तैयार करेगा।

पेपर उद्योग की मांग से बाजार की संभावना-नीलगिरी की लकड़ी का सबसे बड़ा औद्योगिक उपयोग पल्प एवं पेपर निर्माण में माना जाता है, तेजी से बढ़ने और पल्पवुड के रूप में उपयोग होने के कारण इसके लिए औद्योगिक बाजार की संभावना बनी रहती है, यदि सोनहत और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नीलगिरी का उत्पादन होता है तो भविष्य में स्थानीय स्तर पर औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ सकती है,इससे किसानों को लकड़ी खरीदारों,स्थानीय व्यापारियों और औद्योगिक खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल सकता है,लेकिन किसानों को केवल संभावित बाजार को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए,लकड़ी की कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, लकड़ी की गुणवत्ता,मोटाई,मात्रा,परिवहन दूरी, खरीदार और उस समय के बाजार भाव के आधार पर वास्तविक कीमत में अंतर हो सकता है, इसलिए कटाई से पहले संभावित खरीदार और बाजार की स्थिति की जानकारी लेना किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

एक पौधा नहीं, आने वाले वर्षों की 'हरित पूंजी'-नीलगिरी प्लांटेशन को यदि किसान दीर्घकालिक निवेश की तरह देखें तो इसकी उपयोगिता और स्पष्ट होती है,उदाहरण के लिए किसी किसान को उसकी भूमि के अनुसार 1000 पौधे प्राप्त होते हैं,यदि इनमें से अधिकांश पौधे सुरक्षित रहते हैं और वैज्ञानिक तरीके से विकसित होते हैं तो कुछ वर्षों बाद उसके पास एक साथ बड़ी मात्रा में लकड़ी का उत्पादन तैयार हो सकता है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1000 पौधे मिलने का अर्थ 1000 पेड़ों से निश्चित आय नहीं है, पौधों की जीवित रहने की दर,भूमि की उर्वरता, पौधों के बीच उचित दूरी, पानी की उपलब्धता, रोग-कीट नियंत्रण, सुरक्षा, पेड़ों की वृद्धि और कटाई के समय मिलने वाला बाजार भाव ही अंतिम आय तय करेंगे, इसलिए पौधरोपण के साथ देखभाल को भी उतना ही महत्व देना होगा।

किसानों को कमाई का गणित पहले समझना होगा-नीलगिरी प्लांटेशन की संभावित आय का अनुमान केवल पौधों की संख्या देखकर नहीं लगाया जा सकता,किसान को संभावित उत्पादन और भविष्य के बाजार भाव को ध्यान में रखना होगा, सरल शब्दों में-कुल संभावित आय = तैयार लकड़ी की मात्रा म उस समय का बाजार भाव जबकि-शुद्ध आय = कुल बिक्री राशि-भूमि तैयारी-रोपण -रखरखाव-सिंचाई-सुरक्षा-कटाई-परिवहन आदि खर्च,इसलिए किसानों को केवल बड़ी कमाई के दावों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए,अपने क्षेत्र में उपलब्ध क्लोन की गुणवत्ता,अपेक्षित वृद्धि, कटाई अवधि, बाजार की स्थिति और कुल लागत को समझने के बाद ही बड़े पैमाने पर पौधरोपण करना अधिक उचित होगा।

आवेदन के लिए भूमि की जानकारी जरूरी-जो किसान अपनी निजी अथवा खाली भूमि पर नीलगिरी प्लांटेशन करना चाहते हैं, वे संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय अथवा वनमंडल कार्यालय से योजना की वर्तमान पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सामान्य तौर पर आवेदन के लिए आवेदक का नाम एवं पता,निजी भूमि का क्षेत्रफल,संबंधित खसरा नंबर,भूमि से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और संपर्क संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद विभागीय सत्यापन और पात्रता की प्रक्रिया पूरी होने पर उपलब्धता एवं स्वीकृति के अनुसार पौधे प्रदान किए जा सकते हैं, चूंकि योजना की पात्रता और प्रक्रिया प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार बदल सकती है, इसलिए किसान आवेदन करने से पहले संबंधित वन विभाग कार्यालय से वर्तमान नियमों की पुष्टि कर लें।

सोनहत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?-सोनहत वनांचल क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार कृषि,वनोपज और अन्य ग्रामीण गतिविधियों पर निर्भर हैं,ऐसे में निजी भूमि के उस हिस्से का उपयोग,जहां नियमित कृषि कठिन है, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है, यदि बड़ी संख्या में किसान योजनाबद्ध तरीके से पौधरोपण करते हैं और भविष्य में सामूहिक रूप से लकड़ी के विपणन की व्यवस्था विकसित होती है तो परिवहन और खरीदारों तक पहुंच जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकता है,यह पहल तभी अधिक प्रभावी होगी जब पौधे बांटने के साथ किसानों को पौधरोपण की सही तकनीक, दूरी, देखभाल, सुरक्षा और भविष्य के बाजार की जानकारी भी दी जाए।

किसानों को नीलगिरी के फायदे

नीलगिरी के व्यावसायिक पौधरोपण से किसानों को कई संभावित लाभ हो सकते हैं, तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति होने के कारण अपेक्षाकृत कम अवधि में लकड़ी उत्पादन की संभावना रहती है,पल्प एवं पेपर उद्योग में उपयोग के कारण बाजार की संभावना भी बनी रहती है,निजी भूमि के ऐसे हिस्से,जहां पारंपरिक खेती कठिन है,वहां इसे अतिरिक्त आय के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है,सबसे बड़ा तत्काल लाभ यह है कि वन विभाग द्वारा पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने से किसानों की शुरुआती पौध लागत कम होगी,इसके अलावा बड़े पैमाने पर पौधरोपण होने पर भविष्य में कटाई,लोडिंग,परिवहन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं।

पर्यावरणीय संतुलन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

नीलगिरी के आर्थिक लाभों के साथ इसके पर्यावरणीय पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है, नीलगिरी के जल उपयोग,जैव विविधता और मिट्टी पर प्रभाव को लेकर अलग-अलग परिस्थितियों में वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं,इसलिए व्यावसायिक नीलगिरी प्लांटेशन को प्राकृतिक जंगल का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, विशेषज्ञ दृष्टिकोण से निजी भूमि की प्रकृति,स्थानीय जल उपलब्धता और आसपास के पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही वृक्षारोपण किया जाना बेहतर होगा,प्राकृतिक वन क्षेत्र,जलस्रोत अथवा जैव विविधता वाले संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्लांटेशन करने से पहले संबंधित नियमों और विभागीय निर्देशों का पालन जरूरी है, एक ही प्रजाति का अत्यधिक एकल रोपण करने के बजाय स्थानीय परिस्थितियों और भूमि की क्षमता को समझना भी महत्वपूर्ण है।

आज पौधा,कल तैयार होगी संपत्ति

सोनहत में वन विभाग की यह पहल किसानों के लिए तत्काल नकद लाभ की योजना नहीं,बल्कि आने वाले वर्षों के लिए हरित संपत्ति तैयार करने का अवसर है, निशुल्क पौधे मिलने से किसान की शुरुआती लागत कम हो रही है,लेकिन अंतिम सफलता उसके बाद की मेहनत पर निर्भर करेगी,उपयुक्त भूमि, गुणवत्तापूर्ण क्लोन,वैज्ञानिक रोपण, नियमित देखभाल,पौधों की सुरक्षा और बेहतर बाजार संपर्क—इन सभी का संतुलन बनने पर नीलगिरी किसानों की अतिरिक्त आय का मजबूत माध्यम बन सकती है,यदि सोनहत के किसान अपनी निजी भूमि की क्षमता को समझते हुए इस पहल को अपनाते हैं तो आने वाले वर्षों में आज लगाए गए छोटे-छोटे पौधे बड़े वृक्षों के रूप में खड़े होंगे। तब ये केवल क्षेत्र की हरियाली नहीं बढ़ा रहे होंगे,बल्कि किसानों के लिए 'हरित पूंजी' का काम भी कर सकते हैं, मुफ्त पौधों से शुरुआत जरूर हो रही है,लेकिन इस पहल की असली सफलता तब मानी जाएगी जब सोनहत की निजी जमीन पर उगी यह हरियाली किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे।

बचरा पोड़ी में अभाविप की 500 फीट अमर तिरंगा यात्रा,राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंजा क्षेत्र

'न कोई भेद,न कोई दूरी,बस एक पहचान-हम भारतीय हैं' : जिला संयोजक बलबीर पुषाम

-संवाददाता-

कोरिया,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) जिला कोरिया इकाई बैकुंठपुर के नेतृत्व में संपर्क स्थान बचरा पोड़ी में 500 फीट अमर तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, विशाल तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा में विद्यार्थियों, युवाओं और अभाविप कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यात्रा के माध्यम से राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया, तिरंगा यात्रा के दौरान बचरा पोड़ी का वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा। विद्यार्थियों और युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में सहभागिता की तथा देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। 500 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र रही।

विविधता में एकता ही भारत की पहचान-इस अवसर पर अभाविप जिला संयोजक बलबीर पुषाम ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता है। अलग-अलग भाषा,संस्कृति और परंपराओं के बावजूद देशवासियों की पहचान सबसे पहले भारतीय के रूप में है, उन्होंने कहा,'न कोई भेद,न कोई दूरी, बस एक पहचान–हम भारतीय हैं,उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

विद्यार्थियों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा- यात्रा में विद्यार्थियों एवं युवाओं की सक्रिय सहभागिता रही,हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रप्रेम और सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया गया, आयोजकों के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों और युवाओं में राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी,अनुशासन और एकता की भावना को मजबूत करने का माध्यम बनते हैं।

ये रहे प्रमुख रूप से मौजूद-कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य संजय जायसवाल, अभाविप जिला संयोजक बलबीर पुषाम एवं नगर मंत्री आयुषी साहू प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला विस्तारक अशोक यादव,सह मंत्री सिद्धार्थ,विशाल कुमार,दुष्यंत,माही,पंकज साहू, राहुल, भरत एवं दीपन मानिकपुरी सहित अभाविप के कार्यकर्ता और विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए,अभाविप की ओर से आयोजित इस 500 फीट अमर तिरंगा यात्रा ने बचरा पोड़ी क्षेत्र में राष्ट्र भक्ति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की प्रांतीय बैठक बिलासपुर में संपन्न

जिलाध्यक्ष शारदा गुप्ता सहित प्रदेश मंत्री शैलेन्द्र शर्मा और संरक्षक नसीम असदक हुए शामिल

-संवाददाता-

बिलासपुर/कोरिया,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक न्यायधानी बिलासपुर स्थित होटल ग्रांड लोटस में आयोजित की गई,बैठक में प्रदेशभर से पहुंचे व्यापारिक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने व्यापार एवं उद्योग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया, बैठक का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को प्रदेश स्तर पर सामने लाना, उनके समाधान के लिए प्रभावी पहल करना तथा राज्य में व्यापार एवं उद्योग के व्यवस्थित विस्तार की दिशा में रणनीति तैयार करना रहा, प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने सहभागिता की, बैठक के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार, व्यापारियों के हितों के संरक्षण तथा स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली प्रशासनिक एवं व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा की गई।

कोरिया की व्यापारिक समस्याएं प्रदेश नेतृत्व के सामने

बैठक में कोरिया जिलाध्यक्ष शारदा गुप्ता ने जिले के छोटे,मध्यम एवं बड़े व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को प्रदेश नेतृत्व के समक्ष प्रमुखता से रखा,उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यापारियों को दैनिक कारोबार के साथ-साथ विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कई प्रकार की व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है,इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए प्रदेश स्तर से समन्वित प्रयास जरूरी हैं, शारदा गुप्ता ने कोरिया जिले में व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए अधोसंरचना विकास को महत्वपूर्ण बताया, उनका कहना रहा कि बेहतर व्यापारिक वातावरण के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार आवश्यक है। अधोसंरचना मजबूत होने से न केवल मौजूदा व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि नए व्यापार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

व्यापारियों की आवाज को प्रदेश स्तर पर मजबूत करने पर जोर

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को स्थानीय स्तर तक सीमित रखने के बजाय उन्हें चैंबर के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाया जाए, इससे समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभागों और शासन स्तर पर प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सकेगा, बैठक में व्यापार एवं उद्योग के विकास के साथ व्यापारियों के हितों की सुरक्षा,प्रशासनिक प्रक्रियाओं में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधाओं के विस्तार जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

कोरिया से पदाधिकारियों की सहभागिता

प्रांतीय बैठक में कोरिया जिले से जिलाध्यक्ष शारदा गुप्ता के साथ प्रदेश मंत्री शैलेन्द्र शर्मा और संरक्षक नसीम असदक भी शामिल हुए, जिले के प्रतिनिधियों की मौजूदगी से कोरिया के व्यापारिक मुद्दों को प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष रखने का अवसर मिला, बैठक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठनात्मक स्तर पर संवाद और समन्वय को और मजबूत किया जाएगा,साथ ही स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना और सुविधाओं के विकास की दिशा में भी पहल की आवश्यकता है,प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक व्यापारिक संगठनों और व्यापारियों के बीच समन्वय बढ़ाने तथा जिलेवार समस्याओं को प्रदेश स्तर पर उठाने के लिहाज से महत्वपूर्ण रही।

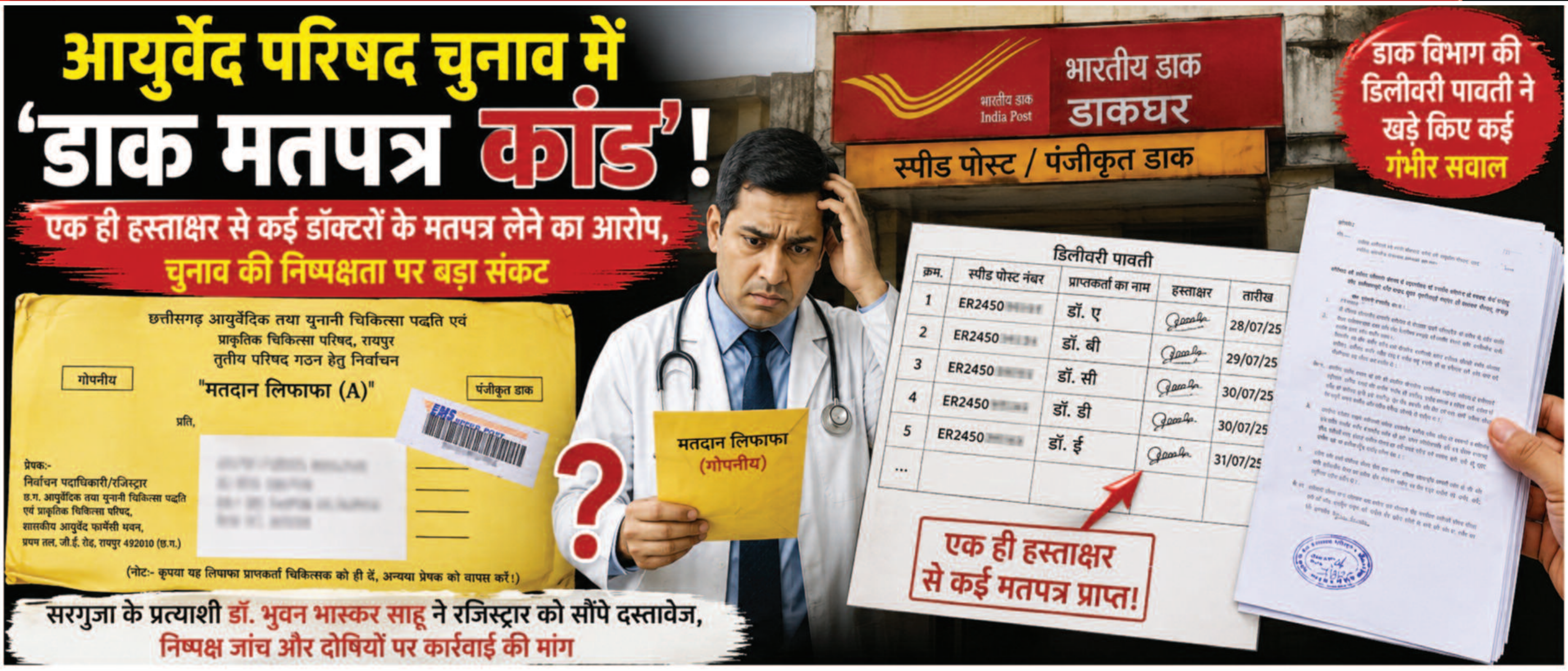

ईवीएम नहीं,बैलेट पेपर की डिलीवरी पर उठे सवाल...एक ही हस्ताक्षर से कई चिकित्सकों के मतपत्र लेने के आरोप ने चुनावी पारदर्शिता पर खड़े किए गंभीर प्रश्न

-न्यूज डेस्क-

सरगुजा/रायपुर/कोरिया ,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। चुनावों में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते हैं,लेकिन छत्तीसगढ़ आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के चुनाव में विवाद ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली है,यहां सवाल ईवीएम का नहीं,बल्कि डाक मतपत्रों की डिलीवरी, उनकी सुरक्षा और संबंधित मतदाता तक उनकी वास्तविक पहुंच को लेकर उठ रहा है। सरगुजा संभाग से चुनाव मैदान में उतरे डॉ. भुवन भास्कर साहू,ग्राम सोनहत,जिला कोरिया द्वारा निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन तथा उसके साथ लगाए गए डाक विभाग के कथित डिलीवरी रिकॉर्ड और पावती दस्तावेजों ने कई सवाल खड़े किए हैं, शिकायतकर्ता का दावा है कि अलग-अलग चिकित्सकों के नाम से भेजे गए डाक मतपत्रों की डिलीवरी से संबंधित दस्तावेजों में एक ही व्यक्ति के समान अथवा मिलते-जुलते हस्ताक्षर दिखाई देते हैं, यदि दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है कि अलग-अलग पंजीकृत मतदाताओं के लिए भेजे गए डाक मतपत्र किसी एक व्यक्ति ने प्राप्त किए,तो मामला केवल डाक वितरण की तकनीकी त्रुटि तक सीमित नहीं रहेगा,इससे मतदाता की गोपनीयता, मतदान के अधिकार और पूरी निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

एक हस्ताक्षर,कई मतदाता और कई मतपत्र-आखिर पहुंचे किसके हाथ?

शिकायत में सबसे गंभीर सवाल डाक मतपत्रों की प्राप्ति प्रक्रिया को लेकर उठाया गया है, शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में अलग-अलग चिकित्सकों के नाम से भेजी गई डाक वस्तुओं की डिलीवरी के संबंध में ऐसे हस्ताक्षर दिखाई देने का दावा किया गया है,जिन्हें शिकायतकर्ता ने एक ही व्यक्ति से संबंधित बताया है,यहीं से विवाद का मूल सवाल सामने आता है–यदि मतपत्र अलग-अलग पंजीकृत मतदाताओं के लिए भेजे गए थे तो उनकी प्राप्ति एक ही व्यक्ति द्वारा किस आधार पर की गई? क्या संबंधित व्यक्ति को इन डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकृत अनुमति थी? क्या डाक वितरण के दौरान प्राप्तकर्ता की पहचान का सत्यापन किया गया? क्या प्रत्येक डाक वस्तु के लिए अलग-अलग प्राप्ति प्रमाण उपलब्ध है? क्या संबंधित चिकित्सकों ने स्वयं अपने मतपत्र प्राप्त किए थे? इन सवालों का अंतिम उत्तर केवल मूल डाक रिकॉर्ड, डिलीवरी मैनिफेस्ट, हस्ताक्षरों के सत्यापन और संबंधित मतदाताओं के बयान से ही सामने आ सकता है।

सरकारी पद के प्रभाव का भी लगाया गया आरोप-शिकायत में केवल डाक मतपत्रों की डिलीवरी को लेकर ही सवाल नहीं उठाए गए हैं,प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव से जुड़े कुछ शासकीय पदों पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अपने पद अथवा प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर चिकित्सकों पर किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रहे हैं,कुछ मतदाताओं को कथित तौर पर विरोध करने की स्थिति में प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है, हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, ऐसे में इनका अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जा सकता है, लेकिन यदि किसी निर्वाचन में मतदाताओं पर दबाव या पद के प्रभाव के इस्तेमाल की शिकायत सामने आती है तो निर्वाचन प्राधिकरण के लिए उसकी निष्पक्ष जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

रजिस्ट्रार को सौंपा गया ज्ञापन, कार्रवाई पर नजर-शिकायतकर्ता के अनुसार निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्ति क्रमांक 44, दिनांक 07 अगस्त 2026 के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इसके साथ डाक वितरण से संबंधित दस्तावेज भी लगाए गए और निर्वाचन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की गई,अब सवाल यह है कि शिकायत मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी की ओर से क्या कार्रवाई की गई,क्या संबंधित डाकघर से मूल रिकॉर्ड मंगाया गया? क्या डिलीवरी मैनिफेस्ट की जांच की गई? क्या संबंधित चिकित्सकों से संपर्क कर यह पुष्टि की गई कि उन्होंने अपना डाक मतपत्र स्वयं प्राप्त किया था? क्या विवादित हस्ताक्षरों की विशेषज्ञ जांच कराने की प्रक्रिया शुरू हुई? इन सवालों पर निर्वाचन अधिकारी एवं रजिस्ट्रार का आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

बिलासपुर,बस्तर और रायपुर से भी शिकायतों के दावे-शिकायतकर्ता पक्ष से जुड़े दावों के अनुसार डाक मतपत्रों की डिलीवरी को लेकर असंतोष केवल सरगुजा संभाग तक सीमित नहीं बताया जा रहा है, बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग से जुड़े कुछ प्रत्याशियों द्वारा भी डाक मतपत्रों की समय पर डिलीवरी, मतपत्र किसे सौंपे गए और वितरण प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए जाने की बात सामने आई है, हालांकि इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है, यदि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से समान प्रकृति की शिकायतें सामने आती हैं तो निर्वाचन प्राधिकरण के लिए पूरे डाक मतपत्र वितरण तंत्र की समीक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।

चुनाव परिणाम से पहले पारदर्शिता की परीक्षा-इस विवाद को केवल किसी एक प्रत्याशी की जीत या हार से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा,चुनाव में मतदाता के मत की गोपनीयता और उसकी स्वतंत्र इच्छा सर्वोच्च महत्व रखती है, यदि शिकायत में लगाए गए आरोप निराधार हैं तो निष्पक्ष जांच से स्थिति स्पष्ट हो सकती है,लेकिन यदि दस्तावेजों में दिखाई देने वाली अनियमितताएं स्वतंत्र जांच में सही साबित होती हैं तो यह सवाल गंभीर होगा कि डाक मतपत्रों की सुरक्षा में चूक कहां हुई और उसकी जिम्मेदारी किसकी थी।

अब निगाहें निर्वाचन अधिकारी और डाक विभाग की जांच पर-आयुर्वेद परिषद चुनाव में उठे विवाद का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं,बल्कि दस्तावेज आधारित और पारदर्शी जांच से ही संभव है। डाक विभाग के मूल रिकॉर्ड और निर्वाचन कार्यालय के दस्तावेजों का मिलान, संबंधित चिकित्सकों के बयान तथा विवादित हस्ताक्षरों का सत्यापन इस मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकते हैं,फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा कि डाक मतपत्रों में चुनावी गड़बड़ी हुई है,लेकिन यदि अलग-अलग मतदाताओं के मतपत्र वास्तव में एक ही व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने के दस्तावेजी संकेत मौजूद हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है, क्योंकि सवाल केवल एक डाक मतपत्र का नहीं है–सवाल उस भरोसे का है जिसके आधार पर एक चिकित्सक अपना मत देता है और अपेक्षा करता है कि उसका वोट उसकी इच्छा के अनुरूप सुरक्षित और गोपनीय रहेगा।

मतपत्र की गोपनीयता पर भी सवाल...

डाक मतपत्र सामान्य पत्र या पार्सल नहीं होता। वह एक पंजीकृत मतदाता के मतदान अधिकार से जुड़ा चुनावी दस्तावेज है,ऐसे में उसकी प्राप्ति से लेकर मतदान और निर्वाचन अधिकारी के पास वापस पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, शिकायतकर्ता का सवाल है कि यदि अलग-अलग मतदाताओं के मतपत्र वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए,तो यह जांचना जरूरी है कि इसके बाद उन मतपत्रों की अभिरक्षा किसके पास रही और वे संबंधित मतदाताओं तक पहुंचे भी या नहीं,यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल किसी डिलीवरी पावती पर समान हस्ताक्षर दिखाई देना अपने आप में चुनावी धांधली का अंतिम प्रमाण नहीं है,यह जांच का आधार जरूर बन सकता है, लेकिन निष्कर्ष के लिए मूल रिकॉर्ड और संबंधित मतदाताओं की पुष्टि आवश्यक होगी।

जांच के लिए इन सवालों का जवाब जरूरी

पूरे मामले में निर्वाचन प्राधिकरण और डाक विभाग को यदि जांच करनी है तो कई बिंदुओं का सत्यापन किया जा सकता है विवादित डाक वस्तु वास्तव में किसे सौंपी गई? प्राप्तकर्ता ने किस पहचान के आधार पर डाक स्वीकार की? डिलीवरी के समय संबंधित मतदाता मौजूद था या नहीं? डिलीवरी मैनिफेस्ट में दर्ज हस्ताक्षर किसके हैं? क्या संबंधित चिकित्सकों ने अपने मतपत्र प्राप्त करने की पुष्टि की है? क्या किसी मतदाता ने लिखित रूप से बताया है कि उसका मतपत्र उसे नहीं मिला? विवादित मतपत्रों की आगे की स्थिति क्या रही? डाक विभाग के पास उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या निर्वाचन कार्यालय के रिकॉर्ड में उन मतपत्रों की वापसी और प्राप्ति दर्ज है? इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

डाक रिकॉर्ड बन सकता है पूरे विवाद की 'कुंजी'

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य डाक विभाग के रिकॉर्ड हो सकते हैं, यदि शिकायत में लगाए गए दस्तावेजों को निर्वाचन प्राधिकरण गंभीरता से लेता है तो प्रत्येक विवादित डाक मतपत्र की डिलीवरी तारीख, समय,प्राप्तकर्ता, हस्ताक्षर, डिलीवरी मैनिफेस्ट और उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मिलान किया जा सकता है,जरूरत पड़ने पर हस्ताक्षरों की विशेषज्ञ जांच भी कराई जा सकती है,इसके साथ ही संबंधित चिकित्सकों के बयान लिए जाने पर यह भी स्पष्ट हो सकता है कि उन्होंने स्वयं अपना मतपत्र प्राप्त किया था या नहीं,यदि किसी चिकित्सक द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि उसके नाम से भेजा गया डाक मतपत्र उसने स्वयं प्राप्त नहीं किया,तो जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से और गंभीर हो जाएगा।

मुख्यमंत्री से लेकर पोस्टमास्टरजनरल तक शिकायत की बात

शिकायतकर्ता की ओर से मामले की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री,स्वास्थ्य मंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,संचालक आयुष तथा पोस्टमास्टर जनरल सहित संबंधित अधिकारियों को भेजे जाने की बात कही गई है,इससे मामला केवल एक प्रत्याशी और निर्वाचन अधिकारी के बीच की शिकायत नहीं रह जाता, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा विषय बन जाता है,यदि जांच में आरोप गलत पाए जाते हैं तो संबंधित पक्ष को भी स्पष्टता मिलेगी और चुनाव प्रक्रिया पर उठ रहे संदेह दूर हो सकेंगे,लेकिन यदि दस्तावेजों और स्वतंत्र सत्यापन में अनियमितता सामने आती है तो फिर जिम्मेदारी तय करने और नियमानुसार कार्रवाई का सवाल उठेगा।

अब तीन सवालों पर टिकी निगाह इस पूरे मामले में फिलहाल तीन सवाल सबसे महत्वपूर्ण हैं–

- पहला-क्या अलग-अलग पंजीकृत मतदाताओं के डाक मतपत्र वास्तव में किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए?
- दूसरा-यदि ऐसा हुआ तो क्या संबंधित व्यक्ति उन मतपत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत था और क्या मतपत्र बाद में वास्तविक मतदाताओं तक पहुंचे?
- तीसरा-शिकायत मिलने के बाद निर्वाचन अधिकारी,रजिस्ट्रार और डाक विभाग इस मामले में किस स्तर की स्वतंत्र जांच कराते हैं? इन तीन सवालों के जवाब ही यह तय करेंगे कि मामला महज डाक वितरण की तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि था अथवा इसके पीछे निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई गंभीर अनियमितता थी,फिलहाल आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं,लेकिन शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर उठे सवालों को निष्पक्ष जांच के जरिए स्पष्ट करना अब निर्वाचन प्राधिकरण की जिम्मेदारी है,चुनाव की निष्पक्षता केवल परिणाम से नहीं,बल्कि मतपत्र के मतदाता तक सुरक्षित पहुंचने की पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी तय होती है।

1200 सालाना संपत्ति कर का आदेश निरस्त, विरोध के बाद भरतपुर जनपद ने लिया यू-टर्न

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने जताई थी आपत्ति,'घटती-घटना' ने भी ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया था

-संवाददाता-

एमसीबी,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन/मकान के नाम पर प्रतिमाह 100 यानी 1200 वार्षिक संपत्ति कर की प्रस्तावित वसूली को लेकर उठे विरोध के बीच जनपद पंचायत भरतपुर ने अपने पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है,जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 8 अगस्त 2026 को जारी ज्ञापन के बाद फिलहाल संपत्ति कर से संबंधित पूर्व निर्धारित प्रक्रिया पर रोक लग गई है। इस मामले को लेकर पिछले दिनों राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठाए गए थे,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाते हुए सरकार और प्रशासन से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की थी, वहीं स्थानीय समाचार पत्र 'घटती-घटना' ने भी ग्रामीणों पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक दबाव और पंचायत स्तर पर कर वसूली को लेकर बन रही स्थिति को प्रमुखता से उठाया था।

8 अगस्त को जारी हुआ निरस्तीकरण आदेश-कार्यालय जनपद पंचायत भरतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक 1115/पं.शाखा/ज.पं./2026-27, दिनांक

08/08/2026 में पूर्व में जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की जानकारी दी गई है,ज्ञापन के अनुसार कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक 627/ पं.शाखा/ ज.पं./ 2025-26, दिनांक 01/07/2026 को निरस्त किया गया है,उक्त पत्र का विषय 'वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु SAMARTH Panchayat Portal एवं ग्राम संपदा में संपत्ति कर संबंधी समस्त कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण किए जाने बाबत' था,8 अगस्त को जारी नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है, निरस्तीकरण आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एमसीबी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एमसीबी,उप संचालक पंचायत,अनु विभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

100 प्रतिमाह कर को लेकर उठे थे सवाल-भवन/मकान के नाम पर प्रस्तावित 100 प्रतिमाह अथवा 1200 वार्षिक कर की व्यवस्था सामने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठे थे,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने कहा था कि ग्रामीण पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते बिजली बिल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में मकान या भवन पर अतिरिक्त कर का बोझ ग्रामीण परिवारों की आर्थिक परेशानियां बढ़ा सकता है,उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि कर वसूली को लेकर ग्राम पंचायत सचिवों पर कितना दबाव बनाया जा रहा है और वसूली नहीं होने की स्थिति में वेतन रोकने अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी चेतावनियों का आधार क्या है।

'घटती-घटना' ने भी उठाया था मुद्दा-इस मामले को स्थानीय समाचार पत्र 'घटती-घटना' ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था,'100 महीना मकान कर पर गरमाई सियासतः गुलाब कमरो ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना' शीर्षक से प्रकाशित खबर में ग्रामीणों पर पड़ने वाले संभावित आर्थिक बोझ,कर वसूली की प्रक्रिया और राजनीतिक विरोध को सामने रखा गया था,अब जनपद पंचायत भरतपुर द्वारा पूर्व आदेश निरस्त किए जाने के बाद यह मुद्दा एक नए मोड़ पर पहुंच गया है,हालांकि निरस्तीकरण आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व आदेश किन कारणों से वापस लिया गया,इसलिए इसे केवल राजनीतिक विरोध का परिणाम मानना या किसी एक पक्ष के प्रयास से जोड़ना उचित नहीं होगा,उपलब्ध आदेश से फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 1 जुलाई 2026 को जारी संपत्ति कर संबंधी पत्र को 8 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

फिलहाल ग्रामीणों को राहत,आगे क्या होगा-निरस्तीकरण के बाद ग्रामीणों और पंचायत स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को फिलहाल राहत मिली है, 100 प्रतिमाह अथवा 1200 वार्षिक संपत्ति कर की जिस प्रक्रिया को लेकर चर्चा और विरोध शुरू हुआ था, उस पर अब तत्काल प्रभाव से विराम लग गया है,अब बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में शासन या पंचायत विभाग की ओर से संपत्ति कर को लेकर कोई नया आदेश जारी किया जाता है या नहीं,साथ ही यदि नई व्यवस्था आती है तो उसकी दर,दायरा,लागू होने की प्रक्रिया और ग्रामीण परिवारों के लिए किसी संभावित छूट अथवा राहत को लेकर क्या प्रावधान होंगे,यह भी महत्वपूर्ण होगा, फिलहाल 8 अगस्त 2026 का निरस्तीकरण आदेश यह जरूर स्पष्ट करता है कि भरतपुर जनपद पंचायत ने 1 जुलाई को जारी संपत्ति कर संबंधी अपने पूर्व निर्देश को वापस ले लिया है और प्रस्तावित 1200 वार्षिक कर की पूर्व प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है।

विश्व आदिवासी दिवस पर गुलाब कमरो का भाजपा सरकार पर हमला,बोले...'सत्ता मिलते ही आदिवासियों को भूल गए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री के बधाई संदेश और सरकारी प्रचार को लेकर पूर्व विधायक ने उठाए सवाल,जल-जंगल-जमीन के मुद्दे पर भी घेरा

-संवाददाता-

एमसीबी,10 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी सम्मान और सरकारी प्रचार को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है,पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला है,उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार आदिवासी समाज को भूल गई है और विश्व आदिवासी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी प्रदेशभर में अपेक्षित सरकारी प्रचार और मुख्यमंत्री का बधाई संदेश नजर नहीं आया।

गुलाब कमरो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाते हुए लिखा कि'सत्ता मिलते ही आदिवासियों को भूल गए,मुख्यमंत्री जी...?'उन्होंने कहा कि अन्य पर्व और महत्वपूर्ण अवसरों पर पूरे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं तथा सरकारी प्रचार पर भारी राशि खर्च की जाती है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर न तो मुख्यमंत्री का बधाई संदेश दिखाई दिया और न ही प्रदेशभर में उसी स्तर का सरकारी प्रचार नजर आया।

आदिवासी चेहरा आगे,सत्ता का खेल कोई और खेल रहा-पूर्व विधायक ने अपने बयान में भाजपा की आदिवासी राजनीति पर भी सवाल खड़े किए,उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एक ओर आदिवासी समाज के नाम और चेहरे को राजनीतिक रूप से आगे रखती है,लेकिन दूसरी ओर आदिवासियों के मूल अधिकारों और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर

अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही, कमरो ने जल, जंगल और जमीन के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों को उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है और इसके बदले आदिवासी समाज को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने इसे भाजपा के कथित'आदिवासी प्रेम' की वास्तविकता से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा,हालांकि,जल-जंगल-जमीन को लेकर लगाए गए इन राजनीतिक आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस बयान से नहीं होती है, ये आरोप पूर्व विधायक गुलाब कमरो द्वारा सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं।

सम्मान के दो शब्द तक नहीं निकले-गुलाब कमरो ने अपने पोस्ट में आदिवासी समाज के सम्मान और पहचान को लेकर भी सवाल उठाया,उन्होंने कहा कि जिस समाज की पहचान और गौरव को सामने रखकर सत्ता की राजनीति की जाती है,उसी समाज के गौरव के दिन सम्मान के दो शब्द तक नहीं निकलना सामान्य भूल नहीं मानी जा सकती,उन्होंने इसे पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर सरकारी स्तर पर अपेक्षित संदेश और गतिविधियां नहीं होना आदिवासी समाज की उपेक्षा का संकेत है।

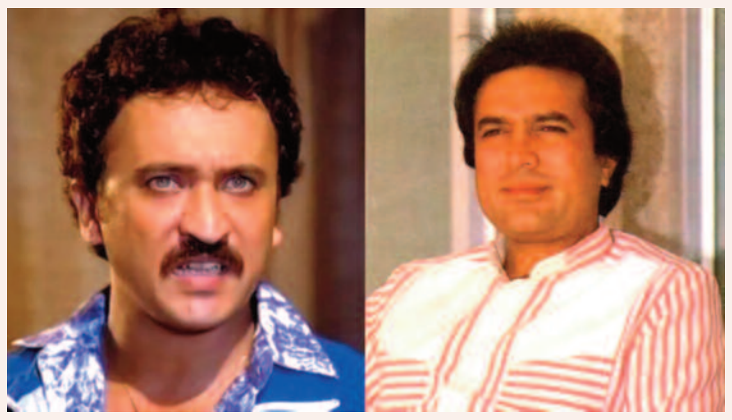

राजेश खन्ना ने मुझे गालियां दीं,स्टारडम के चलते काका में आ गया था घमंड,तेज सप्रू ने बताया किस्सा

अभिनेता तेज सप्रू ने एक हालिया इंटरव्यू में सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है,जब एक्टर ने उन्हें गाली दे दी थी। राजेश खन्ना सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं। फिल्मी गलियारों में उनके स्टारडम की चर्चा होती थी। कहा जाता है कि इसी स्टारडम और सक्सेस ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। हाल ही में, तेज सप्रू एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि एक बार एक्टर ने उन्हें सेट पर गाली दी थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्में कर चुके तेज सप्रू ने रिवील किया है कि अपने करियर के पीक पर सुपरस्टार घमंडी हुआ करते थे।

करियर के पीक पर घमंडी थे काका?

उन्होंने रेडिफ के साथ बातचीत में कहा,राजेश खन्ना को घमंड था। ऐसा होता है, जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं। अक्सर आपसे ज्यादा आपके आस-पास के लोगों का दिमाग फिर जाता है। ऐसा होता है लेकिन साथ ही, मैंने उनसे ज्यादा दरियादिल इंसान कभी नहीं देखा।

राजेश खन्ना ने एक्टर को दी थी गाली

तेज सप्रू ने इंटरव्यू में राजेश खन्ना से जुड़ा सेट का किस्सा भी शेयर किया है। उन्होंने बताया कि सुपरस्टार ने उन्हें गाली दे दी थी। इस बारे में एक्टर ने कहा,एक बार जब हम साथ काम कर रहे थे, तो अचानक मैंने सुना कि पीछे मुझे कोई गाली दे रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह काका जी (राजेश खन्ना) थे।तेज सप्रू ने बताया कि राजेश खन्ना के इस बर्ताव से वह बहुत परेशान हो गए थे। उनके पिता डीके सप्रू ने भी सुपरस्टार के साथ काम किया था। तेज के दिल में काका के लिए बहुत सम्मान था। ऐसे में उनका यूं गाली देना एक्टर को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, इतना सम्मान देने के बाद भी न जाने क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पीछे से मुझे अपशब्द कहे। मैं बहुत परेशान था।

राजेश खन्ना ने सुलझाया था मामला

कश्मीर में हो रहे शूटिंग के दौरान तेज सप्रू,राजेश खन्ना से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। हालांकि,बाद में खुद काका मामले को सुलझाने के लिए आगे आए। इस बारे में उन्होंने बताया,वह मेरे पास आए और बोले,अरे लंबे लड़के...इसे भूल जाओ। मैंने जवाब दिया, सर,आपने बिना किसी वजह के मुझे गाली दी। आपने ही तो कहा था कि हम बस मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा,जो हुआ सो हुआ। भूल जाओ। चलो। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ होटल चलने के लिए कहा।

नागार्जुन की 100वीं फिल्म में धमाका होगा दोगुना,देवी श्री प्रसाद और तब्बू संग फिर जमेगी महफिल,एक नया पोस्टर जारी

तेलुगू सिनेमा के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार देवी श्री प्रसाद नागार्जुन अक्कीनेनी की 100वीं फिल्म किंग100, से जुड़ गए हैं।

इस बात का ऐलान देवी के जन्मदिन पर अन्नपूर्णा स्टूडियोज ने किया और इस मौके पर फिल्म का एक खास पोस्टर भी जारी किया गया।किंग100 के साथ नागार्जुन और देवी की हिट जोड़ी एक बार फिर वापसी कर रही है, जिसने पहले मनमाधुडु और मास जैसी सफल फिल्में दी हैं।किंग100 में नागार्जुन और तब्बू भी 3 दशकों के बाद एक साथ दिखेंगे। दोनों ने आखिरी बार 1996 में निन्ने पेल्लादाटा में साथ काम किया था। हाल ही में तब्बू ने फिल्म की क्लैपबोर्ड की तस्वीर साझा कर शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी। अन्नपूर्णा स्टूडियोज इस फिल्म को बना रहा है, जो नागार्जुन के करियर का एक बड़ा पड़ाव होने वाली है। जल्द ही दर्शकों को कलाकारों और फिल्म की रिलीज की तारीख के बारे में और जानकारी मिलेगी।

नागार्जुन की 100वीं फ़िल्म किंग 100 है और इसे युवा कॉलीवुड डायरेक्टर रा. कार्तिक डायरेक्ट कर रहे हैं। मेकर्स ने इस प्रोजेक्ट में देवी श्री प्रसाद के शामिल होने पर एक नया पोस्टर जारी किया है।इस फ़िल्म में तब्बू एक अहम भूमिका में हैं और नागार्जुन व तब्बू लंबे समय बाद साथ काम कर रहे हैं। फ़िल्म में ऐश्वर्या राजेश फीमेल लीड रोल में हैं, साथ ही सुष्मिता भट्ट और सैंडलवुड स्टार उपेंद्र भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। किंग 100 को पिता-बेटे के इमोशनल रिश्ते पर आधारित फ़िल्म बताया जा रहा है और इसकी 80 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फ़िल्म अन्नपूर्णा स्टूडियोज़ बैनर तले बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है।

मोनालिसा का खुलासा : किरदार को निभाना रहा बेहद चुनौतीपूर्ण

मोनालिसा अपने शो लव टू हेट यू- चैप्टर 2 में एक गहरे और इमोशनली चैलेंजिंग किरदार को निभाने के लिए तैयार हैं। शो चुनने की वजह बताते हुए मोनालिसा ने द्बह्रस् से कहा,मुझे इस शो के बारे में जो बात सबसे अच्छी लगी,वह यह थी कि मेरा किरदार बहुत सीधा-सादा नहीं है। उसे कई तरह की भावनाओं और हालात से गुज़रना पड़ता है। मुझे ऐसे किरदार निभाना पसंद है जिनमें मैं अलग-अलग शेड्स दिखा सकूं। जब मैंने कहानी पढ़ी, तो मुझे लगा कि एक एक्टर के तौर पर मेरे लिए इसमें कुछ दिलचस्प है। कहानी में प्यार है,लेकिन धोखा,दर्द और कई ट्विस्ट भी हैं,इसलिए मैं इसका हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थी।

मोनालिसा ने आगे कहा,जब आप कोई इमोशनल किरदार निभाते हैं, तो आपको यह समझना होता है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। कभी-कभी किरदार गुस्से में होता है, कभी दुखी और कभी कन्फ्यूज्ड। मैंने यह समझने की कोशिश की कि वह किसी खास तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है। मैंने इसे बहुत नैचुरल रखने की भी कोशिश की क्योंकि ये भावनाएं बनावटी नहीं लगनी चाहिए। आप अपने किरदार को जितना बेहतर समझते हैं, उन सीन्स को निभाना उतना ही आसान हो जाता है।

एक्ट्रेस को यह भी लगता है कि कहानी में छिपे राज़ और दुश्मनी किरदारों को और भी पेचीदा बना देते हैं। चैलेंजिंग बात यह है कि एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। परिवार से जुड़े मुद्दे, राज़ और गलतफहमियां होती हैं। एक एक्टर के तौर पर, आपको याद रखना होता है कि आपके किरदार को क्या पता है और क्या नहीं। कभी-कभी आप एक भावना के साथ सीन कर रहे होते हैं,लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि कुछ और भी हो रहा है। यह इसे दिलचस्प भी बनाता है और मुश्किल भी।मोनालिसा ने यह भी माना कि स्क्रिप्ट में ऐसे कई पल थे जिन्होंने उन्हें भी उत्सुक कर दिया। हां,कुछ पल ऐसे थे जब मुझे लगा,अरे,ऐसा होने वाला है? मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती क्योंकि इससे दर्शकों का मज़ा खराब हो जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ऐसे पल हैं जो लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देंगे। स्क्रिप्ट पढ़ते समय भी, मैं जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि हर किसी ने ऐसे हालात का सामना किया है जहां उन्होंने किसी पर भरोसा किया और बाद में उन्हें दुःख या कन्फ्यूजन हुआ। कभी-कभी हमें पूरा सच नहीं पता होता और हम जो देखते हैं,उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। मेरा किरदार भी इसी तरह की भावनाओं से गुज़रता है। मुझे लगता है कि लोग उसके उस पहलू को समझेंगे क्योंकि रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते। लव टू हेट यू : चैप्टर 2 में अमन और रिया के तौर पर हर्ष राजपूत और नियति फतनानी की वापसी हुई,साथ ही अभिमन्यु तोमर, संजना और मोनालिसा भी नज़र आए।

रवि किशन का सुपरहिट भोजपुरी गाना,उदित नारायण ने दी थी आवाज,अब रील्स में उड़ा रहा है गर्दा

रवि किशन का एक भोजपुरी गाना इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लोग इस पर रील्स बना रहे हैं। रवि किशन इस वक्त मीम आइकॉन बन गए हैं। इंटरनेट पर उनके बयान,डांस और सिंगिंग पर फनी मीम्स बन रहे हैं और खूब वायरल भी हो रहे हैं। अब वायरल मीम्स के बीच रवि किशन का एक भोजपुरी गीत चर्चा में आ गया है।

रवि किशन का ये भोजपुरी गीत 23 साल पुराना है। यह गाना अपने चुलबुले बोल और आवाज के लिए आज भी खूब पसंद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस गीत को बॉलीवुड के दिग्गज प्लेबैक सिंगर उदित नारायण ने अपनी आवाज दी थी।

चर्चा में रवि किशन का भोजपुरी गाना

सालों से म्यूजिक लवर्स के बीच धमाल मचाने वाला ये गीत अब 23 साल बाद इंटरनेट पर छा गया है। लोग इस नटखट और चुलबुले गाने पर जमकर रील्स बना रहे हैं। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वो है एगो निमुआ दू चार गो मिर्ची । यह गाना गंगा जइसन मां हमार एल्बम का था।

रिलीज होते ही छा गया था भोजपुरी गाना

इस गाने को रवि किशन पर फिल्माया गया था। उन्होंने अपने अंदाज से गाने को सुपरहिट बना दिया था। गाने में रवि किशन की आवाज उदित नारायण बने थे। इस गाने को सुरिंदर कोहली और धनंजय मिश्रा ने अपनी धुनों से सजाया था,जबकि गाने के बोल विनय बिहारी ने लिखे थे। टी-सीरीज के बैनर तले क्रिएट हुए इस गाने की उस वक्त खूब कैसेट बिकी थी। आज भी यह गीत काफी पॉपुलर है।

पवन सिंह ने भी किया था रीक्रिएट

आप इसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गाना हिट होने के बाद इस पर कई रीमिक्स भी बने हैं। कुछ साल पहले ही इस गाने को पवन सिंह और कल्पना ने रीक्रिएट किया था। उनका गाना भी काफी पसंद किया गया था। आज भी पार्टी,शादी और फंक्शंस में यह गाना खूब सुना जाता है।

क्राइम पेट्रोल को होस्ट करेंगे अजय देवगन,15 एपिसोड की शूटिंग पूरी

बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन अब बड़े पर्दे के साथ-साथ छोटे पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की तैयारी में हैं। अभिनेता लोकप्रिय क्राइम सीरीज 'क्राइम पेट्रोल' को होस्ट करते नजर आएंगे। इस खबर के सामने आने के बाद अजय देवगन के प्रशंसकों के बीच शो को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। खास बात यह है कि अभिनेता ने शो के लिए शुरुआती तौर पर 15 एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। मामले से जुड़े एक भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक, अजय देवगन ने फिलहाल 15 एपिसोड के लिए शूटिंग की है। हालांकि, शो के बाकी एपिसोड्स में भी वह होस्ट के तौर पर नजर आएंगे या नहीं,इसका फैसला अभी तय नहीं है। यह पूरी तरह दर्शकों की प्रतिक्रिया और कार्यक्रम को मिलने वाली ञ्जक्रक्क पर निर्भर करेगा। सूत्र ने बताया कि अजय देवगन ने 'क्राइम पेट्रोल' के नए एपिसोड्स के लिए शूटिंग शुरू कर दी है और अब तक 15 एपिसोड पूरे किए जा चुके हैं। शो के आगे के एपिसोड्स को लेकर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूत्र के अनुसार,अजय देवगन ने अभी 15 एपिसोड की शूटिंग की है। वह सीरीज के बाकी एपिसोड्स के साथ आगे बढ़ेंगे या नहीं, यह दर्शकों के रिएक्शन और नंबर्स पर निर्भर करता है।÷ इससे साफ है कि मेकर्स पहले दर्शकों की प्रतिक्रिया को परखना चाहते हैं। यदि अजय देवगन की होस्टिंग को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और शो की ञ्जक्रक्क मजबूत रहती है,तो अभिनेता आगे भी कार्यक्रम का हिस्सा बने रह सकते हैं।

खेल समाचार

ओडीआई वर्ल्ड कप ढांचा में बदलाव से एसोसिएट देशों को बड़ा झटका

नई दिल्ली,10अगस्त 2026। क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पुरुषों के ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पाथवे में अचानक किए गए स्ट्रक्चरल बदलावों को एसोसिएट देशों के लिए एक बड़ा झटका बताया है,और चेतावनी दी है कि इस कदम से सालों की ग्लोबल तरक्की को नुकसान पहुंचने का खतरा है। यह बयान आईसीसी के जुलाई में एडिनबर्ग में अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस के बाद टूर्नामेंट के फॉर्मेट में बड़े बदलाव के लगभग एक महीने बाद आया है। हालांकि इस इवेंट में शुरू में 14 टीमें होनी थीं,जिन्हें सात-सात के दो ग्रूप में बांटा गया था और उसके बाद एक सुपर सिक्स स्टेज था, लेकिन आईसीसी ने अब इसमें एक सुपर सीरीज और एक सुपर 7 फेज जोड़ दिया है। बदले हुए स्ट्रक्चर के तहत, सबसे नीचे की तीन क्वालिफाइंग टीमें (12वें, 13वें और 14वें स्थान पर) पहले एक राउंड-रॉबिन सुपर सीरीज में मुकाबला करेंगी,जिसमें सिर्फ जीतने वाली टीम ही दो छह-टीम के मेन ग्रुप में टॉप 11 टीमों में शामिल होगी। हर ग्रूप से टॉप तीन टीमें,अगली सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली टीम के साथ,फिर सात टीमों के राउंड-रॉबिन सुपर 7 स्टेज में आगे बढ़ेंगी, जिससे चार सेमीफाइनलिस्ट तय होंगे। जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया,क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हाल के फैसले से बहुत निराश हैं,जिसमें आईसीसी मेन्स 50-ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पाथवे और टूर्नामेंट फॉर्मेट में बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव लागू किए गए हैं, जबकि कॉम्पिटिशन शुरू होने में 18 महीने से भी कम समय बचा है। इसमें आगे कहा गया, ये बदलाव एसोसिएट मेंबर क्रिकेट के लिए एक झटका हैं और हाल के सालों में ग्लोबल गेम को बढ़ाने के लिए हुई प्रोग्रेस को कमज़ोर करने का रिस्क है। ऐसे समय में जब क्रिकेट अपनी पहुंच बढ़ाने, नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करने और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग लैंडस्केप में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है,उभरते देशों के लिए अच्छे मौके कम करना पूरी तरह से गलत मैसेज देता है। बदले हुए फ़ॉर्मेट से एसोसिएट देशों को ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलने के मौके साफ़ तौर पर कम हो रहे हैं। नीदरलैंड और स्कॉटलैंड बोर्ड ने आईसीसी की एडमिनिस्ट्रेटिव ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी पर और सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कम रिसोर्स पर काम करने वाले देशों पर असर डालने वाले फ़ैसले बिना सही सलाह के कभी नहीं लिए जाने चाहिए। अहमियत को दिखाते हैं।

सनवीर बने सबसे महंगे खिलाड़ी

चंडीगढ़ ,10 अगस्त 2026। शेर-ए-पंजाब टी 20 लीग के आने वाले सीजन के लिए नीलामी के पहले हाफ़ में ऑलराउंडर सनवीर सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बने। फ़ज़ल्का फ़ाल्कन्स ने इस टैलेंटेड खिलाड़ी को 13.20 लाख रुपये में अपनी टीम में शामिल किया। अब सनवीर को फ़ज़ल्का फ़ाल्कन्स के लिए स्टार खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ खेलने का मौका मिलेगा। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह मेहता ने कहा,हमने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस सपने को सच करने के लिए बहुत मेहनत की है और अब यह सपना पूरा होने के करीब है। हर क्रिकेटर का सपना मोहाली के स्टेडियम में खेलने का होता है और इस लीग के ज़रिए पंजाब भर के खिलाड़ियों को इस शानदार स्टेडियम में खेलने, ज़रूरी अनुभव हासिल करने और बड़े मंच पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा।अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में, नमन धीर को अमृतसर सूरमास ने 10.80 लाख रुपये में खरीदा, जबकि अमोलप्रीत सिंह 8.20 लाख रुपये में मोहाली किंग्स में शामिल हुए। हरनूर सिंह और अश्वनी कुमार दोनों को बठिंडा रॉयल्स ने 7-7 लाख रुपये में चुना, जबकि सुखदीप बाजवा को जालंधर वॉरियर्स ने 6 लाख रुपये में अपनी टीम में लिया।

चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफ़राज़ ख़ान भारतीय टीम में शामिल

नई दिल्ली,10अगस्त 2026। श्रीलंका के ख़िलाफ़ होने वाली दो मैचों की आगामी टेस्ट सीरीज़ से पहले भारतीय क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है। युवा बल्लेबाज़ साई सुदर्शन चोट के कारण सीरीज़ से बाहर हो गए हैं,और उनकी जगह धाकड़ बल्लेबाज़ सरफ़राज़ ख़ान को अचानक भारतीय टीम में शामिल किया गया है। साई सुदर्शन के बाहर होने की वजह बीसीसीआई द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के अनुसार- अंगूठे में स्ट्रेस रिएक्शन साई सुदर्शन के दाएं पैर के अंगूठे में स्ट्रेस रिएक्शन पाया गया है।

बेंगलुरु में रिकवरी : वे फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेडिकल टीम की देखरेख में रिहैब से गुजर रहे हैं। हालांकि उनकी रिकवरी में सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है।

कोलंबो में टीम से जुड़ेंगे सरफ़राज़ ख़ान

सरफ़राज़ ख़ान कोलंबो पहुंचकर भारतीय टीम से जुड़ेंगे,जिसके बाद पूरी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए गॉल के लिए रवाना होगी।

पहला टेस्ट : सीरीज़ का पहला मुकाबला 15 अगस्त 2026 से खेला जाएगा।

वार्म-अप मैच में जीत : इससे पूर्व रविवार को खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने श्रीलंका-इलेवन को 6 विकेट से पराजित किया।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के लिए अपडेटेड भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल,ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा,गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल,सारांश जैन,आक़िब नबी और सरफ़राज़ ख़ान।

नाम परिवर्तन सूचना/इश्तहार

52 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2026

मैं,शिरलोक सिंह (SHIRLOK SINGH), आत्मजः श्री शिवमंगल सिंह, निवासीः मकान नं. 133/1, दरीमा रोड, लिब्रा, तहसील-अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ 497001 एतद्वारा यह सार्वजनिक सूचना देता हूँ कि मैंने अपना नाम शिरलोक सिंह (SHIRLOK SINGH) से बदलकर श्रीलोक सिंह (SHRILOK SINGH) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नए एवं शुद्ध नाम श्रीलोक सिंह (SHRILOK SINGH) से जाना व पहचाना जाए।

स्थान- अंबिकापुर

दिनांक -10/08/2026

शपथग्रहिता

श्री लोक सिंह

पुराना नाम (SHIRLOK SINGH)

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक /आवेदिका किशोर कुमार मित्रा आ0 /पति स्व0 के0पी0 मित्रा जाति, निवासी नवापारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-नवापारा जवाहर मार्केट, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3/76 रकबा 0.05 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 19.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 04.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक /आवेदिका गोविन्द प्रसाद आ0/ पति हीराचन्द्र गुप्ता जाति,निवासी आजाद वार्ड, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-जवाहर मार्केट, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3/74 रकबा $0.04^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 19.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है । नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 04.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय नज़ूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीमती रश्मि सिन्हा पत्नी श्री संजय कुमार सिन्हा, जाति कायस्थ, निवासी जोड़ापीपल के पास केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग के द्वारा शीट नम्बर -03 मोहल्ला- सत्तीपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 831 / 15 रकबा $0.06^{1/2}$ एकड़ भूमि को बैंक में बंधक रखने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से। दिनांक-21.08.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक- 04.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) **नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 ,जिला-सरगुजा,(छ0ग0)

रा0प्र0क्र0 202608021700001 / ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका कमला देवी पति स्व0 प्रेम सागर गोस्वामी, व अन्य 02, निवासी ग्राम सदर रोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम असोला स्थित भूमि खसरा नंबर 641/36, 641/37, 641/38, 641/39, 641/40 रकबा क्रमशः 0.121, 0.107, 0.153, 0.222, 0.150 हे0 कुल खसरा 05, कुल रकबा 0.753 हे0 भूमि रूपयों की नितांत आवश्यकता होने के कारण अनावेदक नितिन सिंह आ0 नित्यानंद सिंह, निवासी मायापुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा (छ0ग0) को रू0 20,00,000/- (बीस लाख रू0) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 07/09/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 03/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) **अतिरिक्त तहसीलदार ,अंबिकापुर-02**

न्यायालय नायब तहसीलदार, बतौली जिला सरगुजा (छ0 ग0)

ईश्तहार

रा. प्र. क. / अ- 6 / 25-26
ग्राम- तेलईधार, पह0नं0 19

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छ0ग0 राज्य वक्फ बोर्ड के पदेन सचिव द्वारा ग्राम तेलईधार तहसील बतौली स्थित वाद भूमि ख0नं0 786 रकबा 0.271 व ख0नं0 2458/1 में से रकबा 0.198 हे0 भूमि मदरसा (खैरूल अनवार के निर्माण हेतु खुली भूमि) के लिए सुरक्षित के वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 5 (3) (i) (ii) तथा 37 (2) (3) के अनुसार वक्फ संपत्ति के क्षेत्राधिकार कार्यालय (नामान्तरण अधिकारी) को औकाफ की वक्फ संपत्ति का रजिस्टर (एवं राजपत्र) का विवरण भू-अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि के उद्देश्य से छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड अस्तान्तरणीय दर्ज करने हेतु मय आवेदन, बी-1 की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी संस्था या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी तिथि दिनांक 14/08/2026 के पूर्व आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि उपरान्त प्राप्त दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

आज दिनांक 28/07/ 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन पदमुद्रा द्वारा जारी ।

(सील) **नायब तहसीलदार बतौली जिला-सरगुजा (छ.ग.)**

जी नंबर-48707/2

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाथ में तिरंगा थामकर किया भव्य तिरंगा यात्रा का नेतृत्व

140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधता है तिरंगा : मुख्यमंत्री साय

- तिरंगे के रंग में रंगा रायपुर,राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुआ जनसैलाब
- हजारों कदमों के साथ गूंजा 'राष्ट्र सर्वोपरि' का संकल्प...

रायपुर,10 अगस्त 2026। हाथों में लहराता तिरंगा,भारत माता के जयघोष, देशभक्ति के गीत और राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हजारों नागरिकों का उत्साह-राजधानी रायपुर आज पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों नागरिक राष्ट्रध्वज के तले एकजुट हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वयं हाथ में तिरंगा थामकर जनसैलाब के साथ कदम से कदम मिलाया। यात्रा में युवाओं,महिलाओं,बच्चों,बुजुर्गों,पूर्व सैनिकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा हाथों में थामा गया लगभग एक किलोमीटर लंबा तिरंगा पूरे आयोजन का विशेष आकर्षण रहा। तिरंगा यात्रा के शुभारंभ से लेकर समापन तक राजधानी में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई दिया। हजारों हाथों में एक साथ लहराते राष्ट्रीय ध्वज और भारत माता के जयघोष ने पूरे यात्रा मार्ग को राष्ट्रप्रेम की भावना से भर दिया। मुख्यमंत्री साय भी नागरिकों के बीच तिरंगा लेकर आगे बढ़े। इस दौरान नागरिकों में मुख्यमंत्री के साथ चलने और राष्ट्रध्वज के सम्मान में आयोजित इस यात्रा का हिस्सा बनने को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा हमारी आन,बान और शान है। यह केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं,बल्कि भारत की एकता,अखंडता,स्वाभिमान और असंख्य बलिदानों का प्रतीक है। तिरंगे में देश के 140 करोड़ भारतीयों को एक सूत्र में बांधने की अद्भुत शक्ति है। अलग-अलग भाषाओं,संस्कृतियों,परंपराओं और क्षेत्रों की विविधता के बावजूद तिरंगा हम सभी को भारतीय होने के एक साझा गौरव से जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तिरंगा लहराता है तो प्रत्येक भारतीय के मन में स्वाभाविक रूप से राष्ट्र के प्रति गौरव और सम्मान का भाव जागृत होता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का साक्षी है। तिरंगा हमें अपने अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भी स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 'हर घर तिरंगा' अभियान आज एक व्यापक जनअभियान का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान ने तिरंगे को घर-घर तक पहुंचाने के साथ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और मजबूत किया है।

छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता संग्राम में लिखी शौर्यगाथा : साय

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों का स्मरण करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती भी वीरों,जननायकों और बलिदानियों की धरती रही है। देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अदम्य साहस और स्वाभिमान का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों के हित में आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका जीवन हमें बताता है कि राष्ट्रप्रेम के साथ जनसेवा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी सच्ची देशभक्ति का स्वरूप है। मुख्यमंत्री साय ने बस्तर के महान जननायक गुण्डाधुर की शौर्यगाथा को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर संघर्ष का बिगुल फूंका। बस्तर की धरती ने सदैव अपने स्वाभिमान,संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। गुण्डाधुर का साहस और नेतृत्व आज भी छत्तीसगढ़वासियों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह, गुण्डाधुर सहित छत्तीसगढ़ के अनेक ज्ञात-अज्ञात सेनानियों का संघर्ष हमारे गौरवशाली इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। इन महानायकों की शौर्यगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनके आदर्शों से युवाओं को परिचित कराना हमारा दायित्व है।

'तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हर घर तिरंगा' तथा 'तिरंगा यात्रा' के माध्यम से राष्ट्रभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। यह उन स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनायकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है,जिनके त्याग और बलिदान के कारण देश को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि रायपुर के कोने-कोने से बड़ी संख्या में युवा तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। यह उत्साह बताता है कि देश की नई पीढ़ी के हृदय में राष्ट्रप्रेम की भावना कितनी मजबूत है। जिस तिरंगे ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देशवासियों को एकजुट किया था, आज उसी तिरंगे के सम्मान में पूरा रायपुर एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।

'तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति : उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव और एकता का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'हर घर तिरंगा' अभियान ने देशभर में राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊर्जा प्रदान की है। जब प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराता है तो वह केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक के सम्मान, गौरव और संकल्प की अभिव्यक्ति बन जाता है।

बैज बोले...आदिवासी दिवस पर भाजपा ने बधाई तक नहीं दी...

कहा...सत्ता में आते ही आदिवासियों को भूल गई सरकार,2023 से पहले देते थे शुभकामनाएं

रायपुर,10 अगस्त 2026। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस ने भाजपा और आरएसएस पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पहचान को लेकर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 9 अगस्त को पूरी दुनिया में आदिवासी दिवस मनाया गया,लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा के किसी नेता, यहां तक कि आदिवासी नेताओं की ओर से भी समाज को बधाई नहीं दी गई। बैज ने कहा कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की ओर से भी आदिवासी समाज के लिए कोई बधाई संदेश नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि 2023 से पहले भाजपा के नेता भी विश्व आदिवासी दिवस पर शुभकामनाएं देते थे,लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आरएसएस आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहती है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि आरएसएस आदिवासी समाज की संस्कृति और अस्मिता को अलग पहचान देने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी दिवस दुनिया के सामने आदिवासी समाज की एकता, संस्कृति और पहचान को सामने रखने का अवसर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएसआदिवासियों को 'वनवासी' कहकर उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करना चाहती है। बैज ने कहा कि आदिवासी समाज की अपनी स्वतंत्र संस्कृति और सभ्यता है,जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी समाज देश की महत्वपूर्ण आबादी है और उसकी संस्कृति,परंपरा और अस्मिता का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस आदिवासी समाज को मुख्यधारा में बराबरी का स्थान देने के बजाय उसे पिछलग्गू बनाकर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल शुभकामना देने का दिन नहीं, बल्कि आदिवासी अधिकारों,संस्कृति और पहचान पर बात करने का अवसर भी है। हर साल 9 अगस्त को दुनियाभर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों,संस्कृति,परंपराओं और उनकी पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ तबादला

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का किया ट्रांसफर,अगले दो महीनों में चीफ जस्टिस समेत 3 जज होंगे रिटायर

बिलासपुर,10 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार न्यायाधीशों को अलग-अलग हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही ओडिशा हाईकोर्ट के दो जजों के तबादले की भी अनुशंसा की गई है। इनमें जस्टिस कृष्णा राम मोहपात्रा का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अगले दो महीनों के भीतर चीफ जस्टिस समेत दो जज रिटायर होने वाले हैं। इसके बावजूद कॉलेजियम की सिफारिश में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के लिए फिलहाल केवल एक जज का तबादला किया गया है।

दरअसल,सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार न्यायाधीशों को अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। छ्छ्ढ्ढ सूर्यकांत की अध्यक्षता में 6 अगस्त को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। इसी तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। जबकि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को उसी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा की गई है। जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा का जन्म 18 अप्रैल 1965 को हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी न्यायिक रही है। उनके पिता सरत चंद्र मोहपात्रा जज रह चुके हैं। जस्टिस मोहपात्रा ने बीए और एलएलबी की शिक्षा हासिल की है। उन्होंने 7 फरवरी 1988 को ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था।

वकालत के दौरान उन्होंने कानून की कई शाखाओं में काम किया। सिविल, सेवा, आपराधिक और संवैधानिक मामलों समेत अलग-अलग क्षेत्रों में उन्हें करीब 26 साल का अनुभव रहा है। जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा को अभिभावक और आश्रित अधिनियम, हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम,हिंदू दत्तक ग्रहण,भरण-पोषण अधिनियम और किशोर न्याय (बालकों की देखभाल संरक्षण) अधिनियम से जुड़े मामलों का भी अनुभव रहा है। उन्होंने ओडिशा सरकार के साथ-साथ ओडिशा लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा,वे अलग-अलग सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों से जुड़े मामलों में अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर चुके हैं।

ओडिशा हाईकोर्ट के दो जजों का तबादला

कॉलेजियम ने ओडिशा हाईकोर्ट के दो जजों के तबादले की भी सिफारिश की है। जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा का तबादला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट किया गया है। उनके आने से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज को मजबूती मिलने की उम्मीद है। लंबित मामलों के बीच एक नए जज की नियुक्ति से मामलों की सुनवाई और निपटारे में भी मदद मिल सकती है। वहीं, जस्टिस मानस रंजन पाठक का तबादला गुजरात हाईकोर्ट करने की सिफारिश की गई है।

छत्तीसगढ़ में पार्षद पति-पुत्र की व्यवस्था खत्म,अधिसूचना जारी

रिश्तेदारों को प्रतिनिधि बनाने पर रोक,चुनाव महिला जीतीं तो काम भी वही करेंगी

रायपुर,10 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में अब महिला पार्षद चुनी गईं तो उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य उनके नाम पर काम नहीं चला सकेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में 'पार्षद पति' और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधि के पति,पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को उनके प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं बनाया जा सकेगा। सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम में यह नया प्रावधान जोड़ा है।

पति से लेकर करीबी रिश्तेदार तक पर रोक

अधिसूचना में साफ किया गया है कि किसी भी नगरीय निकाय में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति,पुत्र,पुत्री,भाई, बहन या किसी अन्य निकट पारिवारिक सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि या समन्वयक व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने 2022 में बनाए गए प्रतिनिधि नामांकन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पुराने नियम 3 के बाद नया नियम 4 जोड़ा है। इसमें साफ किया गया है कि अगर किसी नगरीय निकाय में कोई महिला जनप्रतिनिधि चुनाव जीतती हैं, तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनके नाम पर प्रतिनिधि बनकर काम नहीं कर सकेगा।

महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने अधिसूचना जारी होने पर इसे महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब महिला जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से जुड़े फैसले खुद लेंगी। वे बैठकों में खुद शामिल होंगी और अपने क्षेत्र की कार्ययोजना भी तैयार करेंगी। उन्होंने कहा कि अब तक कई जगह 'एसपी पति','जेपी पति' और 'पार्षद पति' जैसे संबोधन सुनने को मिलते थे। अब महिला जनप्रतिनिधि खुद अपने पद की जिम्मेदारी निभाएंगी। वे बैठकों में शामिल होंगी,अपने क्षेत्र की जरूरतों को समझेंगी और जनता से जुड़े फैसले खुद लेंगी। उन्होंने इसे महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।

सरकार को मजबूरी में लेना पड़ा फैसला- कांग्रेस

वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सत्ता दल के लोग ही अपनी पत्नियों की जगह सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने आदेश तो जारी किया है,लेकिन मुझे नहीं लगता इसका फर्क पड़ेगा। पिछले दिनों रायपुर नगर निगम मुख्यालय में जल कार्य विभाग की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में दो पार्षद पति भी शामिल हुए थे। इनमें भाजपा और कांग्रेस की महिला पार्षदों के पति शामिल थे। बैठक में प्रमोद साहू और जयंत साहू मौजूद थे। प्रमोद साहू की पत्नी साधना साहू भाजपा से पार्षद हैं,जबकि जयंत साहू की पत्नी रेणु साहू कांग्रेस से पार्षद हैं। यह मामला चर्चा का विषय बना था।

बिलासपुर में पूर्व जनपद-सदस्य पति का गला रेतकर मार डाला,शराब भट्ठी के सामने ऑटो में मिली लाश

बिलासपुर,10 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तोरवा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिनदहाड़े पूर्व जनपद सदस्य के पति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक बाबला साहू ऑटो चलाते थे। उनका शव शराब भट्ठी के सामने खड़े ऑटो के अंदर खून से लथपथ मिला। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक बाबला साहू की पत्नी गीता साहू पूर्व जनपद सदस्य है और भाजपा कार्यकर्ता बताई जा रही है।

हालांकि,हत्या के पीछे राजनीतिक कारण है या आपसी विवाद, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बाबला साहू सोमवार को तोरवा शराब भट्ठी के सामने अपने ऑटो में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दो युवकों से उनका विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों युवकों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। गले में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

तिरंगा यात्रा पर भूपेश बघेल ने कहा...जो कहती है उसके विपरीत चलती है भाजपा,राम नाम जपना,पराया माल अपना

रायपुर,10 अगस्त 2026। तिरंगा यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा,52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। बीजेपी जो कहती है उसके विपरीत चलती है। मोदी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, आज देश बिक रहा है, यह क्षद्म राष्ट्रवाद है। राम नाम जपना पराया माल अपना, अब तो राम का माल भी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने कहा,कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। एक सप्ताह में 6 - 6 हत्याएं हो रही है। एक ही युवती से दो बार गैंगरेप हो रहा है। गृह मंत्री का ध्यान पंचायत की ओर है। अब गांवों में टैक्स लेने का फरमान जारी हुआ है। एक हजार रुपए क्या दिए उसके बदले वसूलना शुरू कर दिए हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल में अब फीस देना पड़ रहा है।

म्यूल अकाउंट गिरोह पर बड़ी कार्रवाई...5 खाताधारक गिरफ्तार 33 साइबर फ्रॉड में 10.18 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा

जांजगीर-चांपा,10 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए देशभर में साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 5 म्यूल खाता धारकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक खातों का इस्तेमाल देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 33 साइबर फ्रॉड के मामलों में किया गया। इन 33 मामलों में कुल करीब 10 करोड़ 18 लाख 19 हजार 809 रुपये की साइबर ठगी सामने आई है। वहीं,आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए म्यूल खातों में ठगी से संबंधित करीब 66 लाख 557 रुपये ट्रांसफर किए जाने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आर्थिक लाभ और कमीशन के लालच में अपने नाम से बैंक खाते खुलवाते थे।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)